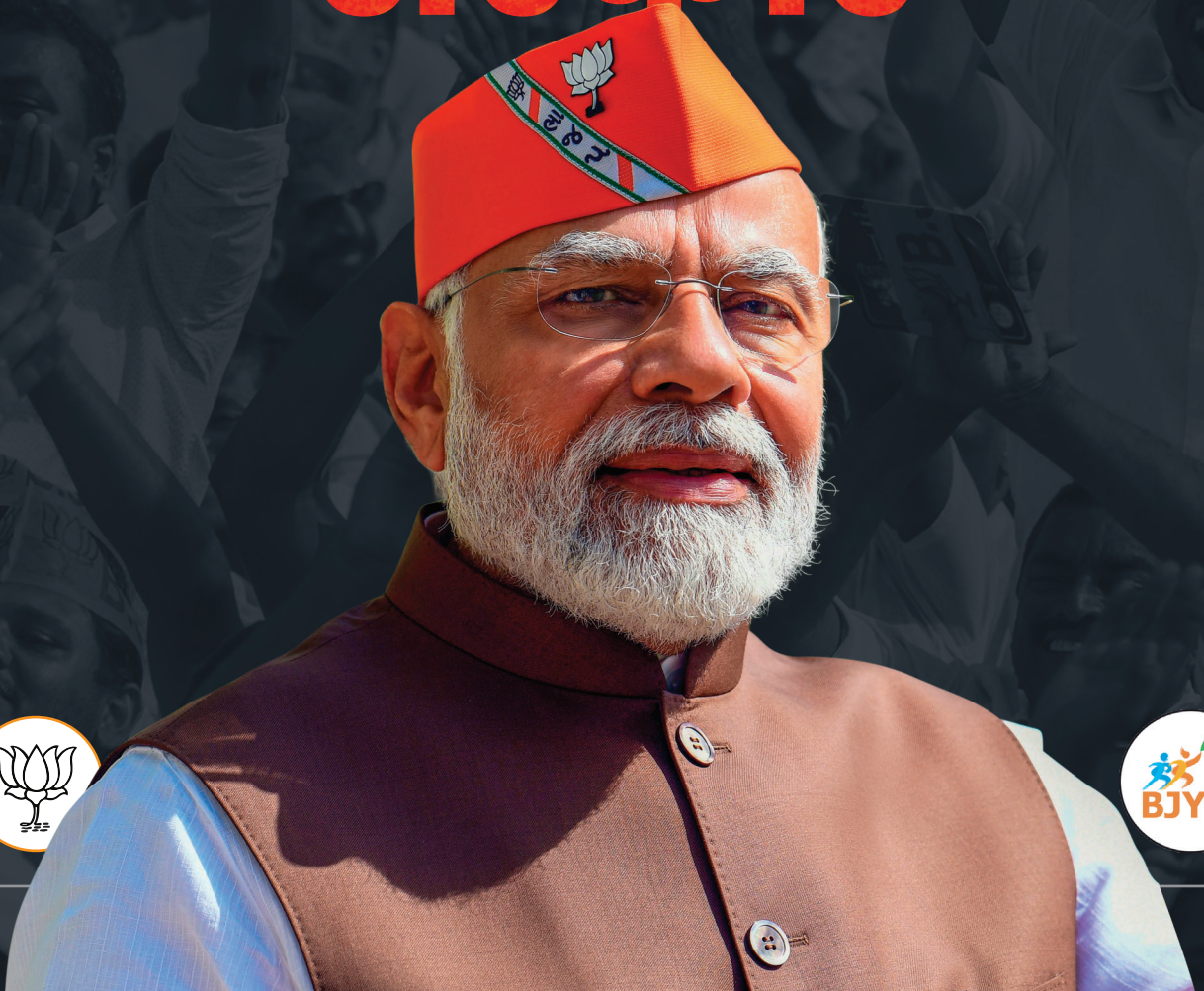


BJYM *Magazine*

MARCH 2024 VOL 30

तीसरी बार मोदी सरकार



CONTENTS

01

Speech of PM Shri Narendra Modi at the BJP National Convention

08

Speech of Shri J.P. Nadda at the BJP National Convention

11

Speech of Shri Amit Shah on the Resolution at BJP National Convention

14

Message from BJYM President Shri Tejasvi Surya

15

Editorial

EDITOR-IN-CHIEF

Abhinav Prakash
National Vice-President, BJYM

ADVISORY BOARD

Varun Jhaveri
National In-charge Policy and Research, BJYM

Animesh Biswas
NEC member, BJYM

EDITORIAL BOARD

Rahul Bhaskar
Adarsh Tiwari
Saurabh Kumar Pandey
Dr. Mrityunjay Guha Majumdar
Kunal Tilak
Mutum Yoiremba

MAGAZINE TEAM

Dhananjay Sharma
Arpit Pratap Singh
Prince Gupta

AVAILABLE ON

BIYM website:
<https://bjym.org/>

BJP E-Library:
<http://library.bjp.org/jspui/handle/123456789/3082>

- 16 स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करती मोदी सरकार शिव प्रकाश
- 19 Strengthening the Fabric of Society: The Imperative of Modi's Third Term for Social Equity
Anup Saha
- 21 Harvesting Progress: Modi's Third Term for Agricultural Renaissance and Farmer Prosperity
Rohit Chahal
- 23 A Trifecta of Triumph: Modi's Third Term as the Keystone of India's Defence Fortitude
Vaibhav Singh
- 26 Securing the Future: Why Modi's Third Term is Essential for India's Tech Ascendancy
PM Sai Prasad
- 29 Continuing the Legacy: Why Modi's Third Term is Crucial for India's Sporting Dreams
Aidan Singh Bhati
- 31 मोदी की गारंटी पर है देश को भरोसा अजय धवले
- 33 A Greener Tomorrow: Why Modi's Environmental Legacy Deserves a Third Term
Kunal Tilak
- 35 Sarvōpakāranīti: Modi-fying Bharat, against Exclusivism
Dr. Mrityunjay Guha Majumdar
- 38 Namo 3.0 & Collective Intentionality
Yuvraj Singh
- 40 Advancing with Modi: A Third Term for India's Unprecedented Journey
Varada Bhaskar Teja
- 41 Tisri Baar Modi Sarkar: A Mandate for India's Continued Resurgence
Ronisha Datta
- 43 Beyond Borders: World Awaits the Historic Mandate
Anhad Jakhmola
- 45 Diaspora and Diplomacy: Uniting Global Indians for a Resurgent Bharat
Alok Virendra Tiwari & Dr Parthiv N Mehta
- 47 Vision 2024: Forging Ahead with Tisri Baar Modi Sarkar
Rajarshi Roychowdhury
- 49 From Vision to Victory: Modi's Third Mandate for a Resilient India
Akanksha Singh
- 51 Forging Ahead with Modi: A Third Term for India's Golden Era
Bharat Sharma
- 53 Judicial and Legal Reforms: The Case for a Decisive Third Term
Krithika Chandrashekara
- 55 Modi's Global Parivar Says 'Tisri baar Modi Sarkar'
Deepakshi Bhardwaj
- 57 Heritage Reborn: A Call for Continuity into the Third Term
Sanjana Sinha
- 59 Consolidating Progress: Why Modi's Vision Warrants a Third Term
M Priyananda Sharma
- 61 सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं
आशीष रावत

आज देश की जनता कह रही है...
भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे...
इसलिए भाजपा ज़रूरी है
.....
महंगाई पर लगाम लगी रहे...
इसलिए भाजपा ज़रूरी है
.....
देश के दुश्मनों में डर बना रहे...
इसलिए भाजपा ज़रूरी है
.....
निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहें...
इसलिए भाजपा ज़रूरी है।
.....
भारत तीसरी सबसे बड़ी
आर्थिक ताकत बने...
इसलिए भाजपा ज़रूरी है।
.....
भारत में तेजी से आधुनिक
इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो...
इसलिए भाजपा ज़रूरी है।
.....
आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो...
इसलिए भाजपा ज़रूरी है।
.....
करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन
मिलता रहे...
इसलिए भाजपा ज़रूरी है
.....
किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे...
इसलिए भाजपा ज़रूरी है
.....
शत-प्रतिशत लाभार्थी तक तेज़ी से हर
लाभ पहुंचे- इसलिए भाजपा ज़रूरी है।

“

इसलिए
भाजपा
ज़रूरी है।



भारत माता की जय !

जो उत्साही साथी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आप बैठेंगे तो अच्छा होगा। आपका ये उत्साह, आपका ये प्यार सर आंखों पर, कृपा करके बैठिए। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मेरी सबसे प्रार्थना है कि भले ही नीचे बैठना पड़े लेकिन अगर आप बैठेंगे तो अच्छा होगा। इधर से मेरे साथियों से आग्रह है...यहां सुनाई देता है मेरी बात...सुनाई देती है...जरा प्रबंधक उस तरफ देखे भाई। जगह नहीं है तो कृपा करके आप ... कहीं पर भी नीचे बैठ जाइए।

भारत माता की जय ! भारत माता की जय !

राष्ट्रीय अधिवेशन में यहां उपस्थित और देश के कोने-कोने से जुड़े प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता, साल के हर दिन, चौबीसों घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन, नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज 18 फरवरी है, इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोट तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ परंपरा सब लोगों के पास पहुंचना है, हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी।

साथियो,

आज मैं...कल मुझे पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिला। कल दोपहर से आप सबके साथ बैठने का अवसर मिला। मैं नड्डा जी और उनकी पूरी टीम को और आप सबको बधाई देता हूँ। जब मैं पदाधिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था। मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता में रहने के बावजूद भी समाज के लिए इतना करते हैं। दिन-रात दौड़ते हैं। संकटों के बीच भी करते हैं। और सिर्फ और सिर्फ भारत मां की जय के लिए करते हैं। ये दो दिन भी जो चर्चा हुआ है, विमर्श हुआ है देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे संकल्प दृढ़ करने वाली बातें हुई हैं। मैं इस भव्य आयोजन के लिए प्रेरक विषयों के लिए आप सबको भी, देशभर के कार्यकर्ताओं को भी नड्डा जी माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूँ।

साथियो,

आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके संल्लेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह-सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दुबारा (भावुक)...उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के गणमान्य

आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है। और इसीलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूँ, समझता हूँ, अनुभव करता हूँ। आपको सुनके आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं। लेकिन शायद ही कोई महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण...किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर-भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। यानि कितने जागरूक थे। अपनी इतनी विराट आध्यात्मिक यात्रा के बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। जीवन भर इतनी सौम्यता के साथ लोगों से मिलते रहे। उन्होंने हमारे युवाओं को परंपराओं से जोड़ा, गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाईं। उनका पूरा जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा जैसा है, जिसने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। आज जब भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुझे ये विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही भारत भूमि को प्रेरणा देते रहेंगे।

साथियो,

पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो गति हासिल की है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है, वो अभूतपूर्व है। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, दुनिया गाजे-बाजे के साथ बोल रही है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प से जोड़ दिया है। और ये संकल्प है- विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाइयों और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, पहली शर्त है- सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। आज विपक्ष के नेता भी NDA सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और NDA को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा।

साथियो,

कई बार लोग मुझसे कहते हैं...अरे मोदी जी आपने इतना तो सब कुछ कर लिया। जो बड़े-बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए। अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी...? साथियों पूरा देश मानता है...10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है..हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है..हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी घटना ज़रूर बताना चाहूंगा। एक बार एक नेता मुझे मिले। मेरे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल में। बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, आप बन गए। आपने इतने दशकों तक संगठन में काम किया। फिर मुख्यमंत्री के

रूप में सेवा की। आप प्रधानमंत्री के रूप में भी दुबारा आ गए। अब जरा बैठो, आराम करो, बहुत कर लिया। ये उन्होंने मुझे कहा था। उनकी वो भावना राजनीति के पुराने अनुभवों से थी।

लेकिन साथियों, हम राजनीति के लिए नहीं राष्ट्रनीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही, उनसे प्रेरणा लेकरके मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म, सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूँ। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूँ, जागता हूँ जूझता रहता हूँ। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों-बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवाभाव से दिन-रात एक कर रहे हैं। 10 वर्षों में हमने जो हासिल किया, साथियों, वो तो एक पड़ाव मात्र है, मंजिल तक पहुंचने का एक नया विश्वास है, अभी हमें अपने देश के लिए, कोटि-कोटि भारतीयों के लिए, हर भारतीय का जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने हैं, संकल्प है। इसके लिए बहुत से निर्णय बाकी हैं।

साथियो,

आज भाजपा, युवा शक्ति, नारीशक्ति, गरीब और किसान शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रही है। पहले लोगों को लगता था कि सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। हमने सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की भावना से हर व्यवस्था को पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच से बाहर निकाला। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है, इतना ही नहीं हमने उनको पूजा है। आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों को पहले किसी ने नहीं पूछा। हमने उनके लिए पीएम जनमन योजना बनाई। लाखों विश्वकर्मा परिवारों को किसी ने नहीं पूछा। हमने उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। रेहड़ी-ठेले-फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमने उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई।

साथियो,

पहले की सरकारों ने महिलाओं के हितों की, उनके जीवन में आ रही परेशानियों की भी कभी चिंता नहीं की। हमारे यहां बेटियों को गर्भ में ही मार डालने की कितनी विराट समस्या थी। हमने इसके लिए हमने सामाजिक चेतना और कड़े कानून, दोनों का सहारा लिया। पहली बार देश में बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ जैसा एक जनआंदोलन चला, जिसका एक बहुत ही सार्थक प्रभाव हुआ। हमने बालिकाओं के, महिलाओं के पोषण पर विशेष बल दिया। हमने पोषण अभियान चलाया ताकि गर्भवती महिलाओं को उचित मदद मिल सके। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। गर्भ के समय महिलाओं को उचित पोषण मिले, इसके लिए मातृवंदना योजना के तहत सवा 3 करोड़ से अधिक बहनों को सीधी मदद दी। हमने

सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत लगभग 5 करोड़ गर्भवती महिलाओं का हेल्थ चेकअप किया। प्रयास यही था कि माता और शिशु, दोनों के जीवन पर पहले जो खतरे रहते थे, उन्हें कम किया जा सके। 2014 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर कितनी चिंताएं होती थीं। हर कोई चिंतित रहता था। हमने रेप जैसे संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाईं।

साथियो,

मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों पर लाल किले से नाराजगी व्यक्त की थी। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया। हमने 4 करोड़ घर बनाए, जिनमें से 3 करोड़ से ज्यादा घर महिलाओं के नाम रजिस्टर में है। हमने महिलाओं के नाम 3 करोड़ ज्यादा घर रजिस्टर करवाकर उनको घर का मालकिन बनवाया। हमने 10 करोड़ परिवारों की बहनों को पहली बार नल से जल दिया। हमने 12 करोड़ परिवारों की बहनों को टॉयलेट दिया। ये चारदीवारी नहीं इज्जत घर है। हमने 1 रुपए में सुविधा सेनिटेरी पैड्स की योजना शुरू की। हमने 25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन, महिला लाभार्थियों को दिए।

साथियो,

बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, बेटियों को नौकरी करने में आसानी हो, इसके लिए भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से 10 करोड़ बहनों को जोड़ा। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। खादी को जो फिर से नया जीवन मिला है, उसका फायदा भी सबसे अधिक गांव की बहनों को ही हुआ है। हमने प्रेग्नेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। पहले फैक्ट्रियों में या दूसरी जगहों पर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए अनेक अड़चनें थीं। हमने श्रम कानूनों में सुधार करके, इनको भी दूर किया। हमने पैरामिलिट्री फोर्स में महिलाओं की भर्ती दोगुने से अधिक की। हमने सेनाओं के अग्रणी मोर्चों में महिलाओं की तैनाती को सुनिश्चित किया। हमने सैनिक स्कूलों और मिलिट्री अकेडेमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए।

साथियो,

इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ नारी शक्ति से पूरे देश को प्रेरणा दे रहा था। आने वाले समय में हमारी माताओं-बहनों-बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। 'मिशन शक्ति' से देश में नारीशक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संपूर्ण इकोसिस्टम बनेगा। अब 15 हजार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे। ड्रोन दीदी खेती में वैज्ञानिकता और आधुनिकता लाएगी। अब देश में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएंगी। पीएम विश्वकर्मा योजना से परंपरागत कला और शिल्प से जुड़ी बहनें सशक्त होंगी। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बेटियों को शिक्षा और स्किल के मामले में सबसे अधिक

फायदा होगा। गांव के पास ही बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से बेटियां स्पोर्ट्स में कमाल करेंगी।

साथियो,

आज जब मैं बीते 10 वर्षों पर नजर डालता हूं, तो कितना ही कुछ याद आता है। ये 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम रहे। जो काम सदियों से लटके थे... हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में भी 500 साल बाद धर्मध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहब राहदारी खोली। 7 दशक के इंतजार के बाद देश को आर्टिकल-370 से मुक्ति मिली। लगभग 6 दशक बाद राजपथ, कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया। 4 दशक बाद आखिरकार, वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी हुई। 3 दशक बाद आखिरकार, देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। 3 दशक बाद आखिरकार, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला। तीन तलाक की बुराई के विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने ही दिखाया। दशकों से नए संसद भवन की ज़रूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया। ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि वो ऐसी अनेक सिद्धियों का निमित्त बन सके।

साथियो,

कोई भी देश हो, वो अपना भविष्य तभी संवार सकता है, जब वो अपने इतिहास को सहेजकर रखता है। बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को सहेजा भी है, संवारा भी है। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया। हमने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाई। हमने अंडमान में नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामकरण किया। हमने दांडी में नमक सत्याग्रह स्मारक का निर्माण किया। हमने बाबा साहेब आंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ को विकसित किया। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में म्यूजियम बनवाया। सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे कार्यकाल में बनी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हमारी सरकार ने घोषित किया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का अवसर हमें मिला। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में याद करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 26 दिसंबर को हमने साहिबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने का फैसला भी हमारी ही सरकार ने किया। और 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे भी हमारी ही सरकार के प्रयासों से घोषित किया।

साथियो,

विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना ना जानते हों, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने, जो वादा हम कर रहे हैं उसका जिज्ञा भी करने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है। वो वायदा है- विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि

ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक, देश जब आजादी का 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। ये मोदी की गारंटी है। और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं...तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है, भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार। चहुं दिशा में विस्तार।

साथियो,

हम इसके लिए कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, इसका हिसाब लगाना भी ज़रूरी है। भारत को (ये आंकड़ा याद रखिए) वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया तो, 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में 2 ट्रिलियन डॉलर और जोड़ लिए हैं। 1 के लिए 60 साल, 10 साल में 2 और जोड़ दिया। जब भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, 11 से 10 पर आने में दम उखड़ गया उनका, हम 11 से पांच पर ले आए। जब 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बना पाते थे। आज भारत पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है तो भारत का इंफ्रा बजट 11 लाख करोड़ को पार कर रहा है। इसी वजह से, आज गरीबों के करोड़ों घर बन रहे हैं। आज गरीबों के घर तक पानी पहुंच रहा है। आज देश में रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, कॉलेज-यूनीवर्सिटीज़ बन रहे हैं। गांव तक सड़कें बन रही हैं। जब भारत दुनिया की टॉप तीन अर्थव्यवस्थाओं में आएगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास कार्यों के लिए हमारे पास कितनी ज्यादा पूंजी होगी। इसलिए, भारत के टॉप तीन इकॉनॉमी में आने का मतलब है..भारत के हर परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा, भारत के हर परिवार की आय, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और आधुनिक बनेगा...भारत में रोजगार के लिए नए सेक्टर खुलेंगे, रोजगार के और ज्यादा मौके बनेंगे। भारत के युवा को भारत में ही फंडिंग के ज्यादा से ज्यादा अवसर आएंगे। भारत की महिलाओं को हर मोर्चे पर आगे बढ़कर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। हमारे किसान Latest Technology से जुड़कर काम करेंगे। कृषि उत्पाद में वैल्यू एडिशन करेंगे। लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए देश में पर्याप्त संसाधन और व्यवस्थाएं मौजूद होंगी।

साथियो,

मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत अभियान की बागडोर भी भारत के युवाओं ने संभाल ली है। पिछले डेढ़ साल में विकसित भारत के संकल्प से जुड़े सुझावों के लिए (और लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम बात...लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर हम डेढ़ साल से चुपचाप काम कर रहे हैं, सरकार की मशीनरी को लगाया है) और आपको जानकर खुशी होगी अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत कैसा हो, रोडमैप कैसा हो इनीशिएटिव कैसा हो, नीतियां कैसी हो इस पर विचार विमर्श हुआ है। लोगों ने अपने आइडिया दिए हैं। और आपको जानकर और खुशी होगी कि इन 15 लाख में से आधे, 35 वर्ष से कम

आयु के हैं। पूरी युवा सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन लाखों युवाओं ने विकसित भारत का रोडमैप सुझाया है।

साथियो,

युवा ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है, जो लक्ष्य तय करता है, उन्हें अपनी आंखों के सामने प्राप्त भी करता है। हम 2029 में भारत में यूथ ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने के लिए काम कर रहे हैं। हम 2030 तक हमारी रेलवे को नेट जीरो के टारगेट पर लाकर कार्बन मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम 2030 के बजाय अपनी टारगेट डेट से 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20 प्रतिशत Ethanol Blending का लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे। भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी नीतियां बना रहा है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में हमारे देश में अनगिनत ग्रीन जॉब्स बनेंगी।

साथियो,

विकसित भारत वो नहीं होगा जिसका भविष्य भाग्य के भरोसे हो। इसलिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को हम तेजी से कम कर रहे हैं। इसलिए हम देश के लिए बड़े लक्ष्य बना रहे हैं और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी कर रहे हैं। भविष्य में हम एक ऐसा भारत देखेंगे, जिसे लाखों करोड़ रुपये का खाद्य तेल बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पाम ऑयल मिशन की मदद से हमारे किसान ही इतने सशक्त हो जाएंगे, कि वो देश के पैसों की बचत कर सकें। बीते कुछ वर्षों में दलहन, तिलहन और श्री अन्न के लिए विशेष नीतियां बनाई गई हैं। जिससे छोटे-छोटे किसानों को मदद हो रही है। भविष्य में भी हमारे किसानों को इनसे और लाभ मिलेगा। किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने देश के कोने-कोने में अमृत सरोवर अभियान भी शुरू किया है। आजादी का अमृत मोत्सव हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम दिल्ली के अंदर कोई बड़ा ताबूत खड़ा करके नाम लिखवा सकते थे कि आजादी के अमृत काल में मोदी जी ये बनाकर गए। हमने आजादी के अमृत वर्ष को जनांदोलन बनाया। और काम क्या किया... तालाब बनाए। हर गांव में जब तालाब बनते हैं न तो वो किसान को सुरक्षित करते हैं, शुद्ध पानी की गारंटी देते हैं, जमीन उर्वरक बना देते हैं। हमने भविष्य को सोच करके ऐसे काम हम करते हैं। इस अभियान के तहत देश में 60 हजार से ज्यादा नए सरोवर बनाए जा चुके हैं। 60 हजार तालाब...शायद ही किसी सरकार के नसीब में ये काम करने का सौभाग्य आया होगा। ये सरोवर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की मदद करेंगे।

आज ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े अभियान और सोलर रूफटॉप मिशन के कारण देश RENEWABLE ENERGY के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द भारत, दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनेगा और इससे पूरी दुनिया में नई Computing Revolution को भी भारत गति देने का निमित्त बनने वाला है। पोर्ट लेड ग्रोथ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, आने वाले समय में हर क्षेत्र को नई ऊंचाई मिल सकेगी।

साथियो,

भाजपा, आज देश का एकमात्र दल है जो एक भारत-श्रेष्ठ भारत की

भावना के प्रति इतना आग्रही भी है और इतना समर्पित भी है। मैं पिछले महीने के अपने अनुभवों को कभी भूल नहीं सकता। इस दौरान मुझे भगवान श्री राम से जुड़े कई स्थलों के भ्रमण करने का अवसर मिला। मेरा 11 दिनों का अनुष्ठान चल रहा था। उस अनुष्ठान के दरम्यान मैं नासिक, लेपाक्षी, त्रिप्रयार, श्रीरंगम, रामेश्वरम धनुषकोडी...में इन जगहों पर एक सामान्य साधक के तौर पर गया था। इस दौरान मुझे दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से जो स्नेह मिला आशीर्वाद मिले, इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, ये पॉलिटिकल पंडितों के पैरामीटर वो कभी आ नहीं सकता है। जब मैं सड़कों से गुजर रहा था, लोग अपने वचन से, अपने भावों से मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। इस दौरान मुझे कंब रामायण का पाठ सुनने का अवसर मिला। ये ठीक उसी जगह पर हुआ जहां महान कवि कंबन ने 800 वर्ष पूर्व अपने रामायण की रचना की थी। आप कल्पना कर सकते हैं उसी स्थान पर बैठ कर मैं कंब रामायण को सुन रहा था ...उस भाव विश्व को मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। ये एक ऐसा अद्भुत क्षण था, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पूरी तरह समाहित थी। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने कम-अधिक मात्रा में इसे महसूस किया होगा। हम हमेशा विभिन्न तरीके से देशवासियों को करीब लाने का निरंतर प्रयास करते हैं। एकता सूत्र में बांधने के लिए हमारी कोशिश रहती है चाहे संयुक्त राष्ट्र में जाकरके पहली बार कोई तमिल में बोलता है। जगद्गुरु बशवेश्वर का संदेश दूर-दूर तक पहुंचाने के लिए हम लेकर जाते हैं। काशी तमिल संगमम का आयोजन हो, काशी तेलुगु संगमम का आयोजन हो, या फिर बीएचयू में सुब्रह्मण्यम भारती के नाम पर चेंबर की स्थापना हो, हम जी 20 करते हैं तो देश के कोने कोने में जाकर करते हैं, विदेश से मेहमान आते हैं तो दिल्ली को ही देश नहीं मानते हम हर राज्य में लेकर जाते हैं। हम राजभवनों में हर राज्य के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। कोई राजभवन होगा नागालैंड भी वहां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और गुजरात का भी मनाया जाएगा, महाराष्ट्र का भी मनाया जाएगा, गोवा का भी मनाया जाएगा हर राज्य भवन में राष्ट्रीय एकता का उत्सव बना दिया जाता है। हम अपनी विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे दिल के बहुत करीब है, इसे मजबूत बनाने के लिए हम काम करते रहेंगे।

साथियो,

एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारी गवर्नेंस में भी दिखती है। हर क्षेत्र के विकास पर हमारा पूरा फोकस है। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण आपके सामने है। पहले की सरकारों में नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया था। क्योंकि पार्लियामेंट की सीटें कम हैं, उनका इंटरैस्ट ही नहीं था। हम वोट और सीटों के हिसाब से काम नहीं करते हमारे लिए देश का हर कोना समृद्ध हो विकसित हो यही हमारा भाव है। आज चाहे सियाचिन हो, या फिर देश के आकांक्षी जिले हों, कोई हमसे दूर नहीं है। वो गांव, जिन्हें पहले आखिरी गांव कहा जाता था, हमारे लिए देश के पहले गांव बन गए हैं। मेरे सारे कैबिनेट के मंत्री उन गांवों में रात बिता कर आए कुछ को तो माइनस 15 डिग्री में रुकना पड़ा। क्योंकि आत्मसात करना चाहते हैं। हमारे लिए देश का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है, हर हिस्से पर हमारा फोकस है।

साथियो,

जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखता है, और जिसके लिए लोकतांत्रिक मूल्य महत्व रखते हैं, वो भी अगर न्यूट्रल है तो पब्लिकली हमारी प्रशंसा करते हैं, न्यूट्रल नहीं है तो खानगी में तो कर ही देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, हमने समय के साथ खुद को सराकात्मकता के साथ बदलने का प्रयास किया है। हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नए और आधुनिक विचारों के लिए खुला रखा है। आजादी के बाद वर्षों तक, जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोग ही सत्ता के केंद्र में रहे। उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया। हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बनें और परिणाम लाकर दिखाएं। इससे व्यवस्था में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहा। हमारी कैबिनेट में रिकॉर्ड संख्या में नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं। नागालैंड से पहली महिला सांसद राज्यसभा में सांसद बनी हैं। हमें गर्व है कि हमने पहली बार त्रिपुरा के मंत्री को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया। पहली बार हमारी सरकार में अरुणाचल प्रदेश को कैबिनेट मिनिस्टर मिला। पहली बार, गुर्जर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। हमारी सरकार में ही, गोवा से एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हमें गर्व है कि हम बीजेपी की एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं, जहां मंत्रालय में रिकॉर्ड ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

साथियो,

हमारी सरकार सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास हमारे काम से ही झलकता है। हमें गर्व होता है जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के द्वारा लाखों सिख श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती हैं। आप कल्पना कीजिए 70 साल तक भारत की सीमा रह कर सिख अनुयायी दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करते थे। हमने स्थिति बदली है। हमने लंगर की वस्तुओं से GST भी हटाया। हमने स्वर्ण मंदिर के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया, जिससे विदेशियों को सेवा करने का अवसर मिला। पहली बार, वीर बाल दिवस मनाकर हमने सत्य और न्याय के लिए बलिदान देने वाले साहेबजादों के शौर्य को सम्मान दिया। आज केरल का बच्चा भी जानता है कि साहिबजादे का बलिदान कैसा था। नागालैंड का बच्चा भी जानता है कि साहिबजादों ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। अफगानिस्तान से गुरुग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे सम्मान से वापस लाए। इसके साथ ही, हमारी सरकार ने हज की प्रक्रिया में सुधार करके यात्रा को सुविधाजनक बनाया। आज बिना मेहरम के हज करना भी संभव हुआ है। इससे महिलाओं के लिए भी हज करना आसान हो गया है। और हजारों महिलाएं गईं।

साथियो,

2014 में जब मैंने शपथ ली, तो हमारे कई आलोचक कहते थे, मोदी जी एक राज्य के बाहर उनका क्या अनुभव है, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दुनिया... मोदी क्या करेगा। लेकिन वो सब देख लें... विदेश नीति को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कही जाती थीं। मैं कुछ दिनों पहले ही UAE और कतर से वापस आया हूँ। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत

हुए हैं, ये आज दुनिया देख रही है। आज पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे संबंध अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में हैं। 2015 में जब मैं UAE गया था, आप हैरान हो जाएंगे, मेरे से पहले उसके 34 साल पहले तक कोई भी पीएम वहां नहीं पहुंचा था। सोचिए कि किस तरह हमने उस पूरे क्षेत्र को छोड़ रखा था। कांग्रेस की सरकारें, पूरे वेस्ट एशिया को सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में देखा करती थीं। उन्हें भारतीयों की शक्ति और उनके विश्वास पर भरोसा ही नहीं था। लेकिन आज भारत इस क्षेत्र से संबंधों का नया अध्याय लिख रहा है। पहले लोग सोचते थे कि बस तेल का इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां से सस्ते लेबर भेज देते हैं। ताकि उनको रोजी रोटी मिल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ट्रेड, टेक्नॉलजी, टूरिज्म और ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं। और हम निरंतर विकास कर रहे हैं। यहां तक कि अरब के 5 देशों ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान तक दिया है। ये सम्मान मोदी का नहीं, 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का सम्मान है।

भाइयो और बहनो,

विदेश नीति के जो भी जानकार हैं, वो विदेश से मिल रहे संकेत भी पकड़ रहे होंगे। आज अलग-अलग देशों में सत्ता और विपक्ष के दल ये खुलकर मानते हैं कि भारत के सशक्त होने से पूरी दुनिया का हित होने वाला है। ये पूरी दुनिया मानने लगी है। आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान, भारत की ताकत बढ़ रही है। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। और इन सबके बीच कोई देश हमारी सरकार से बातचीत के लिए...आप जानकर हैरान होंगे...अभी तो चुनाव बाकी है लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए हैं, निमंत्रण देकरके। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है। आएगा तो मोदी ही। आएगा तो मोदी ही।

साथियो,

कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, बीजेपी के हर प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस, अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस...परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस...भ्रष्टाचार की जननी है। और कांग्रेस, तुष्टिकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार, कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है, मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूँ। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई-नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है, उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोडमैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर, तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं।

साथियो,

कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रही है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और

सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि पांच साल पहले इन लोगों ने क्या क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ना मिल पाएं। इन्होंने अपप्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को खत्म किया जा रहा है। ये लोग तो एचएएल के बाहर, फोटो तक खिंचाने चले गए। लेकिन देखिए कि एचएएल आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए कितने सारे ऑर्डर उनके यहां बुक किए गए हैं। देखिए कि उसकी मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। जब एयरस्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे। कांग्रेस, भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती।

साथियो,
कांग्रेस कितनी कन्फ्यूज है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, सिद्धांतों और योजनाओं को लेकर नहीं चल रही है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है मोदी से तीखी नफरत करो। मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ। मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। वहीं कांग्रेस में एक और वर्ग है। जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकलो। इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानि कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस, इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। इसलिए, गाली-गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है।

साथियो,
लाल किले से मैंने कहा था- यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में आज वो समय आ गया है, जब हमें अपने देश का भाग्य

बदल देना है। मैंने देशवासियों को लाल किले से कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 11 घंटे काम करेगा, अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा, अगर आप 14 घंटा काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। मेरे साथियों, देशभर के मेरे कार्यकर्ताओं, देश उज्ज्वल भविष्य की आशा लगाए लोगों से मैं कहना चाहूंगा। आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है। आपको हर लाभार्थी तक पहुंचना है। मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है, करोगे। हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। और इसमें आपको नमो एप से भी बड़ी मदद मिलेगी। आप नमो एप के जरिए मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी उन लाभार्थी तक जरूर पहुंचाएं। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो, जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो। आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम और आने वाले 5 वर्षों के प्लान के बारे में बताना है। आपको उन्हें नमो एप पर विकसित भारत का ब्रांड एंबेसेडर बनाना है। मतदान के दिन, इन सभी मतदाताओं को बूथ पर लाकर हमें कमल निशान पर मतदान करवाना है। जहां एनडीए के साथी हों उनके निशान पर मतदान करवाना है। आपको याद रखना है, हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही लोगों को नहीं जोड़ना बल्कि देश बनाने के लिए भी लोगों को जोड़ना है। जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है। सबका साथ-सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। और इसके लिए भाजपा जरूरी है, भाजपा सरकार जरूरी है।

साथियो,
आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अबकी बार...400 पार...इस मिशन पर हमें जुट जाना है। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
भारत माता की जय ! भारत माता की जय ! भारत माता की जय !

Source: narendramodi.in



In a momentous occasion graced by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Bharatiya Janata Party's National President Shri Jagat Prakash Nadda ji, the two-day National Convention of the party commenced at Bharat Mandapam in New Delhi. The programme was attended by the Union Home Affairs and Cooperation Minister Shri Amit Shah, along with the Union Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, and all central ministers of the party, Chief Ministers of BJP-ruled states, Deputy Chief Ministers, State and District Presidents, as well as all party office-bearers. Nearly 10,000 delegates from across the country participated in the convention.

Before the convention was formally kicked off, the BJP flag was unfurled by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, and the National President Shri Jagat Prakash Nadda. The convention kicked off with the ceremonial lighting of the lamp and the rendition of the national anthem. Shri Nadda conveyed appreciation to office bearers and party workers for their dedication and hard work, for their collaborative endeavors in propelling the BJP's triumphant momentum. He lauded Prime Minister Shri Narendra Modi's steadfast dedication to the party's growth. Shri Nadda elaborated on the BJP's journey, from its challenging origins to becoming the world's largest political party, crediting its success to the commitment of its members and the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi.

Speech of

Shri J.P. Nadda

at the BJP National
Convention



Key points of address:

- Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the nation is advancing on the path of development, and a new dimension has been established in politics. The tenure of the Bharatiya Janata Party under the esteemed leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is marked by numerous accomplishments.
- Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the BJP will surpass the mark of 370 and the NDA will secure more than 400 seats, in the upcoming Lok Sabha elections.
- The bill to abolish Article 370, which had been stalled for years due to political animosity, was swiftly passed in both the houses of Parliament within three days under the leadership of esteemed Prime Minister Shri Narendra Modi ji. This was made possible by the adept strategy of Union Home Minister Shri Amit Shah ji, leading to the permanent abolition of Article 370.
- The current stature that the party has achieved and the strength with which the organization today stands firmly at the grassroots level is only possible due to sacrifices of our respected leaders, their austerity, and the commendable contributions of every party karyakarta.
- BJP, with its roots in the Bharatiya Jan Sangh, has weathered significant challenges over seven decades. In the past decade, under Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji's leadership, the party has seen remarkable growth and acceptance.
- Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji has shifted the narrative and prioritized the upliftment of GYAN - Gareeb (the poor), Yuva (the youth), Annadata (the farmers), and Nari Shakti (women empowerment), thus ensuring the nation's overall development.
- In 1989, at the BJP's national executive in Himachal Pradesh, it was decided to work on the construction of the Shri Ram Mandir. Despite mockery from opposition parties, after

500 years of struggle, the dream of the nation was finally fulfilled. On January 22, 2024, Prime Minister Shri Narendra Modi ji observed an 11-day penance to honor Bhagwan Ram's homecoming, leading to the realization of the temple and the vision of Ram Rajya. Many congratulations to Prime Minister Shri Narendra Modi ji from crores of party karykartas.

- In the 2009 elections, the Bharatiya Janata Party garnered 18.8% of the country's support. However, under the leadership of the Hon'ble Prime Minister, this surged to 31.3% in 2014. In 2019, the party surpassed its own record by securing 303 seats in the Lok Sabha elections, up from 282, and its vote share rose from 31% to 37%.
- Prior to 2014, the BJP governed only 5 states in the country. However, today, the NDA government holds power in 17 states, with the BJP leading majority governments in 12 of them. Before 2014, the BJP represented 17.5% of the population, but this figure has now surged to 58%.
- Respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji has diligently fulfilled all promises with unwavering dedication and hard work. This has led to the empowerment of villages, the poor, farmers, and women. For the first time since Independence, there is a prevailing belief among marginalized communities that the government under Shri Narendra Modi truly represents them.
- Under the Ujjwala Yojna, the Narendra Modi's government has provided gas connections to more than 11 crore women to empower them. Under the Saubhagya scheme, over 2 crore 62 lakh people have been provided with electricity connections to their homes, and approximately 18 thousand villages have been electrified. Additionally, under the Jal Jeevan Mission, piped water has been delivered to the homes of 11 crore people.
- Prior to 2014, India held the 11th position among the world's largest economies. However, today,

the nation ranks among the top five global economies. Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the BJP is poised to form a government with a resounding majority for the third time in 2024, propelling India's economy to become the world's third-largest.

- During the Covid pandemic, Bharatiya Janata Party karyakartas, without caring for their lives, distributed crores of masks, and sanitizers, distributed food, and delivered medicines to thousands of elderly people. This demonstrated that the party's organizational efforts are ultimately aimed at benefiting the community.
- Through the Navmatdata Sammelan, the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji addressed over 3.2 million new voters. The Yuva Morcha played a pivotal role in ensuring the success of this program by effectively implementing it on the ground.
- Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the BJP has successfully connected around 10 crore women to self-help groups. Now, the party was committed to empowering 3 crore women as 'Lakshpati Didis'.
- Due to the policies implemented during the tenure of the BJP, higher education enrollment has surged by 44% in the SC category, 65% in the ST category, and 44% in the OBC category. The Jan Dhan-Aadhaar-Mobile scheme has effectively curbed corruption, ensuring that approximately ₹30 lakh crore directly reaches the accounts of the underprivileged.
- Under the leadership of the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the BJP secured victory and formed the government at the Center for two consecutive terms. Additionally, the BJP achieved success in Uttarakhand in two consecutive elections. The overwhelming victory in the assembly elections of Rajasthan, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh was credited to the public's confidence in the assurances of the respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji.

- According to the International Monetary Fund report, India is recognized as a "Bright Spot," boasting the highest growth rate at 6.3 percent among major countries worldwide. Additionally, the Morgan Stanley report placed India at the forefront among developing nations.
- Respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji has bestowed the prestigious Bharat Ratna upon the distinguished sons of India, former Prime Ministers Shri Choudhary Charan Singh and Shri PV Narasimha Rao, in recognition of their lifelong contributions to the nation. Additionally, the commendable decision to honor Jananayak Karpoori Thakur, respected Shri Lal Krishna Advani, and agricultural scientist Shri MS Swaminathan with the Bharat Ratna is a noteworthy gesture.
- In the pursuit of India's development, the Bharatiya Janata Party has accomplished the construction of an extensive network spanning 3 lakh 75 thousand kilometers of roads in rural areas. Additionally, the installation of optical fiber in 2 lakh panchayats has facilitated internet connectivity and 1300 new world-class railway stations are being built.
- The BJP's voting percentage in West Bengal has surged significantly, escalating from 10% to 38.5%, accompanied by a notable increase in the number of assembly seats, rising from 3 to 77. In Gujarat, the BJP has maintained continuous power since 1997, showcasing a longstanding electoral success. The party achieved a historic victory in Haryana in 2014 and, in Assam, has formed the government twice since 2014, an accomplishment once deemed unattainable.
- Presently, the BJP has successfully extended its reach to over 8 lakh 40 thousand booths, and there are plans to further expand to 10 lakh booths soon. The dedicated efforts of the party Karyakartas will play a significant role in achieving this ambitious goal.

Source: Press release, bjp.org

**केंद्रीय गृह एवं
सहकारिता मंत्री श्री
अमित शाह** द्वारा भारत
मंडपम में आयोजित
भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय अधिवेशन में
आए प्रस्ताव **“भाजपा:
देश की आशा, विपक्ष
की हताशा”** विषय पर
दिए गए संबोधन के
मुख्य बिंदु



देश की जनता ने संकल्प लिया है कि
2024 में आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी
जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना
है और एनडीए सरकार को 400 के
पार ले जाना है।
.....

मोदी 3.0 में देश आतंकवाद,
अलगाववाद और नक्सलवाद से पूर्ण
मुक्त हो जायेगा
.....

देश में चुनावों के दौरान हिंसा फैलाने
वाला गठबंधन है INDI अलायन्स
.....

मोदी जी के परिश्रम, नीतियां और
परफॉरमेंस के कारण जनता बार-बार
भाजपा को चुनती है
.....

100 साल बाद भी सरकारें गिराने के
कांग्रेस के रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं
पायेगा
.....

मोदी जी की सोच, कर्मठता और
परिश्रम से होगा विकसित भारत का
निर्माण
.....

मोदी जी दीपक के लौ की तरह खुद
जल कर अंधेरे को दूर कर रहे हैं
.....

परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन
कभी भी देश का भला नहीं कर
सकता
.....

देश में अस्थिरता की जनक है कांग्रेस
.....

देश और सरहदों की सुरक्षा मोदी
सरकार की प्राथमिकता
.....

मोदी जी ने देश की राजनीति से
जातिवाद, परिवारवाद और
तुष्टिकरण को समाप्त किया
.....

अगर भाजपा में परिवारवाद होता, तो
एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी
प्रधानमंत्री नहीं बन पाता

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की गरिमामय उपस्थिति में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ-साथ पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और जिलाध्यक्षों से लेकर राष्ट्रीय स्तर के तमाम पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को किसानों को सालाना ₹6,000 प्रदान करने, अर्थव्यवस्था को पांचवें स्थान पर पहुंचाने और नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने का श्रेय दिया, साथ ही "वंशवादी पार्टियों के घमंडिया गठबंधन" पर भी निशाना साधा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में हुए परिवर्तनकारी बदलावों का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया। पिछले 75 वर्षों में, भारत ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। प्रत्येक सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि आज देश का समग्र विकास, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल और कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को प्रत्येक किसानों को सालाना ₹6,000 प्रदान करने, अर्थव्यवस्था को पांचवें स्थान पर पहुंचाने और नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने का श्रेय दिया। श्री शाह ने "वंशवादी पार्टियों के घमंडिया गठबंधन" पर भी निशाना साधा। उन्होंने योग्यता-आधारित, प्रदर्शन-आधारित राजनीतिक ढांचे के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और इसकी तुलना वंशवादी पार्टियों के नेतृत्व की भूमिकाओं में पारिवारिक उत्तराधिकार को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति से की।

श्री शाह ने कुछ पारिवारिक पार्टियों के अपने सदस्यों को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र लक्ष्य की ओर इशारा किया, इसकी तुलना भाजपा के लोकतांत्रिक लोकाचार से की, जहां एक बूथ कार्यकर्ता भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। श्री अमित शाह ने विपक्ष द्वारा प्रमुख सुधारों का विरोध करने के पैटर्न के खिलाफ चेतावनी दी और वंशवादी गठबंधन शासित राज्यों में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं का प्रदर्शन किया। एनडीए और वंशवादी घमंडिया गठबंधन के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए श्री शाह ने एनडीए को विकल्प के रूप में चुनने पर जोर दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की निरंतर प्रगति का वादा किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपलब्धियां गिनवाते हुए और ऐलान किया कि 2024 में मोदी 3.0 की सरकार आने वाली हैं और पहली बार देश का गौरव दुनिया ने महसूस

किया है। श्री शाह ने संदेशखाली हिंसा पर कहा कि टीएमसी के राज में महिलाओं के अधिकार का हनन किया जा रहा है। इंडी अलायंस देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है।

केन्द्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने भाजपा की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक बूथ का कार्य संभालने वाला कार्यकर्ता भी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत और आधार पूरी तरह लोकतांत्रिक हैं और इन्हीं लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर भाजपा के संगठन की इमारत मजबूती से खड़ी है। श्री शाह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति का पद उसकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। आज भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मू एक जनजातीय परिवार से आती हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन कर पूरे देश की हर जनजाति का सम्मान और आदर किया है। राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च पद यानि उपराष्ट्रपति पर आसीन श्री जगदीप धनखड़ देश के जाट समाज से आते हैं और देश के अन्नदाता किसान के बेटे हैं। एक किसान को बेटे को उपराष्ट्रपति बनाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशभर के किसानों का सम्मान किया है और उन्हें सशक्त किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में देश का समग्र विकास और हर क्षेत्र का अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है। केन्द्रीय गृहमंत्री ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई और इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को सालाना ₹6 हजार की राशि दी गई, जो दिखाता है कि केन्द्र की भाजपा सरकार किसानों, गरीबों और ग्रामीणों के समुचित विकास और उत्थान के लिए संकल्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था के लेकर कई बड़े कदम उठाए और आर्थिक सुधार के लिए समर्पित नीतियां लागू जिसके परिणामस्वरूप आज भारतीय अर्थव्यवस्था 11 वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर आ गई है। भाजपा सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में देश का हर वर्ग का तेजी से विकास हुआ है। श्री शाह ने कार्यकर्ताओं से समक्ष भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का संकल्प पेश करते हुए कहा कि इस अधिवेशन के बाद भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 में विकसित भारत के संकल्प को लेकर चुनाव में जाएगा। पूरे देश में संशय खत्म हो चुका है और आज पूरे देश ने एकजुट होकर तय कर लिया है कि 2024 में श्री नरेन्द्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे।

श्री अमित शाह ने भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में दो खेमे आमने-सामने हैं। जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों वाला घमंडिया गठबंधन है। गृहमंत्री श्री

शाह ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक है जबकि एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है। श्री शाह ने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 2014 से 2024 तक के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश में नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्ति की ओर है और आखिरी सांसें गिन रहा है। श्री शाह ने कहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जातिवाद, वंशवाद आदि से मुक्ति दिलाई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' की स्थापना की और धीरे-धीरे ब्रिटिश शासन से जुड़े राष्ट्रीय प्रतीकों को हटाकर हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कर रहे हैं।

श्री अमित शाह ने बताया कि जहां एक ओर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत बनाना है वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन के हर दल के प्रमुख नेता का लक्ष्य मात्र अपने बेटे या बेटे को सत्ता की गद्दी पर बिठाना है। कांग्रेस की सोनिया गांधी राहुल को पीएम, शरद पवार अपनी बेटे को सीएम, ममता बनर्जी अपने भतीजे को सीएम और स्टालिन, लालू एवं उद्धव अपने बेटे को सीएम बनाने का लक्ष्य लेकर राजनीति कर रहे हैं। इन सबके अलावा मुलायम सिंह यादव तो अपने बेटे अखिलेश को सीएम पद पर बिठाकर ही गए। श्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जिस नेता का लक्ष्य अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो कभी भी गरीब कल्याण, जनउत्थान और देश का विकास नहीं कर सकता। वंशवादी राजनीति पर तंज कसते हुए श्री शाह ने कहा कि इस देश में 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G का मतलब घोटाला नहीं है। 2G का मतलब 2 जेनरेशन पार्टी है और 4-4 पीढ़ी तक इनका नेता नहीं बदलता है।

श्री अमित शाह ने कहा अब देश में “डेवलपमेंट अलायंस (NDA) बनाम डायनेस्टिक अलायंस (INDIA)” है। श्री शाह ने कहा कि देश की बागडोर संभालने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से बेहतर कोई नेता नहीं है। अगर भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी नहीं होती

तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। इंडी गठबंधन सात परिवारवादी दलों का गठबंधन है और इन पार्टियों में पिछली चार पीढ़ियों से नेता नहीं बदला है, इन दलों का मुख्य उद्देश्य अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित करना है और जब बेटों का कल्याण ही मुख्य लक्ष्य हो तो देश का कल्याण कैसे होगा?

श्री शाह ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के 10 वर्षों के शासन के बाद आज देश का प्रत्येक व्यक्ति विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहा है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में जनता ने विपक्षी दलों को इस प्रकार नकार दिया है कि दूर-दूर तक घमंडिया गठबंधन को सत्ता प्राप्ति की संभावना नहीं दिखती है और इसी कारण इन विपक्षी दलों के नेता आजकल हर चीज का विरोध करने लगे हैं। विपक्षी दलों ने अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक खत्म करने और ओबीसी कमीशन का विरोध तो किया ही लेकिन इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने में भी इन लोगों ने काफी व्यवधान उत्पन्न किया। श्री शाह ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा कर केवल इस ऐतिहासिक पल का हिस्सेदार बनने से खुद को अलग ही नहीं किया है बल्कि कांग्रेस ने देश को महान बनाने की प्रक्रिया से भी खुद को दूर कर लिया है। भारत की जनता विपक्ष का रामलला की प्राणप्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने और इसके पीछे की इनकी नीयत को देख भी रही है और याद भी रख रही है।

श्री अमित शाह ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि यह सभी परिवारवादी पार्टियां इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं करने में लगी रही कि कभी भी देश में जनमत स्वतंत्र रूप से उभरकर न आए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दस साल के कुशल प्रशासन में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर देश में अभूतपूर्व विकास के नए आयाम स्थापित किये हैं। अंत में उन्होंने कहा कि 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी 3.0 शुरू होगा और 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा होगा।

Source: Press release, bjp.org



नमस्कार!

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले दस साल भारतवर्ष के लिए परिवर्तनकारी रहे हैं। पिछले दस वर्षों में देश की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था ने जिस तरह का बदलाव देखा है वह हर मायने में ऐतिहासिक है। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो भारत के राजनीतिक इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: 'मोदी से पहले' और 'मोदी के बाद'।

मोदी के पहले देश का माहौल निराशा का था, तनाव और आशंका का था। लेकिन आज देश उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीवंत है। हर दिन हम देश की नई उपलब्धियों को देखते और सुनते हैं, चाहे वह चंद्रयान की उपलब्धि हो, एशियाई खेलों में हमारी अभूतपूर्व पदक संख्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी उपलब्धि हो, या हमारे स्टार्टअप्स की उपलब्धियां हों। हम हर दिन उपलब्धियों और सफलता की कहानियाँ सुन रहे हैं। आज निराशा ने आशा को मार्ग दे दिया है। मोदी के पहले निराशा थी, मोदी के बाद उम्मीद है।

पहले की सरकारों सरकार के अधिकांश प्रयास समस्याओं को टालने के थे, न कि समस्याओं का समाधान करने के। लेकिन मोदी सरकार दशकों और सदियों पुरानी समस्याओं को भी हल करने से पीछे नहीं हटती है। यह एक ऐसी सरकार है जो समस्याओं को टालने में विश्वास नहीं करती है, यह एक ऐसी सरकार है जो समस्याओं के समाधान में विश्वास करती है। निर्णायकता मोदी सरकार का परिभाषित चरित्र है।

जीवन के सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी वर्गों में हम आज एक नया आत्मविश्वास देख रहे हैं। भारत आज न केवल रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात कर रहा है बल्कि सुशासन के मॉडल और मापदंडों को भी विश्व पटल पर स्थापित कर रहा है। दुनिया यह भी देख रही है कि कैसे भारत ने एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्थापित किया है जो दुनिया में बेजोड़ है। हमने डेटा संरक्षण कानून में जो विधायी तकनीकी - कानूनी समाधान तैयार किए हैं, उसने भी विश्व पटल पर एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। हमने कल्याणकारी राज्य का भी नवीन मॉडल विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है।

आज देश का युवा कह रहा है कि देश बदल नहीं रहा है अपितु देश बदल चुका है। मोदी से पहले सत्ता थी, मोदी के बाद सेवा है। मोदी से पहले समस्या थी, मोदी के बाद समाधान है। मोदी से पहले मालीनता थी, मोदी के बाद स्वच्छता है। मोदी से पहले विवाद था, मोदी के बाद विश्वास है। मोदी से पहले अयोध्या में तंबू था, मोदी के बाद भव्य राम मंदिर है। मोदी से पहले आतंक था, मोदी के बाद शांति है। मोदी से पहले गरीबी थी, मोदी के बाद समृद्धि है। मोदी से पहले बेरोजगारी थी, मोदी के बाद कौशल विकास है। मोदी से पहले अपराध था, मोदी के बाद सुरक्षा है। मोदी से पहले विभाजन था, मोदी के बाद एकता है। मोदी से पहले निराशा थी, मोदी के बाद आशा है। मोदी से पहले अव्यवस्था थी, मोदी के बाद व्यवस्था है। मोदी से पहले अन्याय था, मोदी के बाद न्याय है। मोदी से पहले तुष्टीकरण था,

भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या का संदेश



मोदी के बाद सबका साथ, सबका विकास है। मोदी से पहले परिवारवाद था, मोदी के बाद लोकतंत्र है। मोदी से पहले परावलंबन था, मोदी के बाद आत्मनिर्भरता है।

भारत का युवा आज दृढ़निश्चय कर चुका है कि देश में न सिर्फ तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी अपितु इस बार 400 सीटों के लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। मैं आप सभी के यह अनुरोध करता हूँ कि 2024 के लोक सभा चुनाव में मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर बन कर जन-जन तक जाएं और विकसित भारत के निर्माण के लिए उन्हें भाजपा की मतदान के लिए प्रेरित करें।

वंदे मातरम

तेजस्वी सूर्या

सांसद लोकसभा, बेंगलुरु दक्षिण

EDITORIAL

As India approaches another pivotal moment in its democratic journey, the prospect of Prime Minister Narendra Modi securing a third term at the helm of the world's largest democracy merits a thorough examination. The tenure of PM Modi has been characterized by bold reforms, significant policy shifts, and a vision of progress that has resonated with many. From the abrogation of Article 370 to landmark economic reforms, each step has been a testament to a governance model that seeks to redefine India's path forward.

PM Modi's first term laid the foundation with a series of economic reforms aimed at propelling India's growth. The introduction of the Goods and Services Tax (GST) revolutionized India's tax structure, making it simpler and more unified. The Make in India initiative sought to position India as a manufacturing hub, aiming to attract foreign investment and create millions of jobs. Meanwhile, the Jan Dhan Yojana aimed to bring the unbanked into the banking system, a significant step towards financial inclusion.

The second term saw Modi's government taking more decisive actions on several fronts, leading to deepening reforms and addressing long-standing issues. The abrogation of Article 370 marked a historic policy shift, aiming to fully integrate Jammu and Kashmir into India, promising better governance and development for its people. The CAA provided citizenship to persecuted minorities from neighbouring countries, underlining PM Modi's commitment to humanitarian intervention. Facilitating the resolution of the Ayodhya dispute and the subsequent groundbreaking ceremony for the Ram Mandir represented a significant cultural and political milestone, fulfilling a long-standing promise by the BJP.

A continued push for digitalization, reforms in foreign direct investment policies, and the ambitious Aatmanirbhar Bharat (Self-reliant India) initiative aimed at boosting domestic

manufacturing and reducing dependency on imports have infused new dynamism in the Indian economy. Under PM Modi's leadership, India has adopted a more assertive stance against terrorism, including conducting surgical strikes and the Balakot airstrike, showcasing a willingness to cross borders to protect national security. These actions have not only bolstered India's defence posture but also elevated PM Modi's image as a leader committed to safeguarding the nation.

PM Modi has actively sought to enhance India's global stature, engaging in high-profile diplomatic efforts, including strengthening ties with the United States, engaging with the Middle East, and playing a crucial role in international forums like the G20 and COP climate summits. His leadership in establishing the International Solar Alliance highlights India's commitment to addressing global challenges such as climate change.

PM Modi's government has launched several welfare schemes that have made significant strides in improving the quality of life for millions. Initiatives like the Swachh Bharat Mission, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, and Pradhan Mantri Awas Yojana have contributed to sanitation, reduced air pollution, and provided affordable housing, respectively. In the last ten years, 25 crore people have been lifted out of multidimensional poverty.

The realization of PM Modi's vision—ranging from economic transformation to social welfare—necessitates a sustained period of stable and decisive governance. A third term would not only allow for the maturation of these policies but also enable PM Modi to take several other required reforms to lay the foundations of a Viksit Bharat, with India becoming the third largest economy.

As India contemplates its future, the argument for PM Narendra Modi's third term is built on a foundation of significant policy reforms, national security enhancements, diplomatic achievements, and a clear vision for a progressive, inclusive, and globally competitive India. The journey thus far suggests a path laden with opportunities for further development, stability, and global leadership under PM Modi's continued stewardship.

स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करती मोदी सरकार

शिव प्रकाश

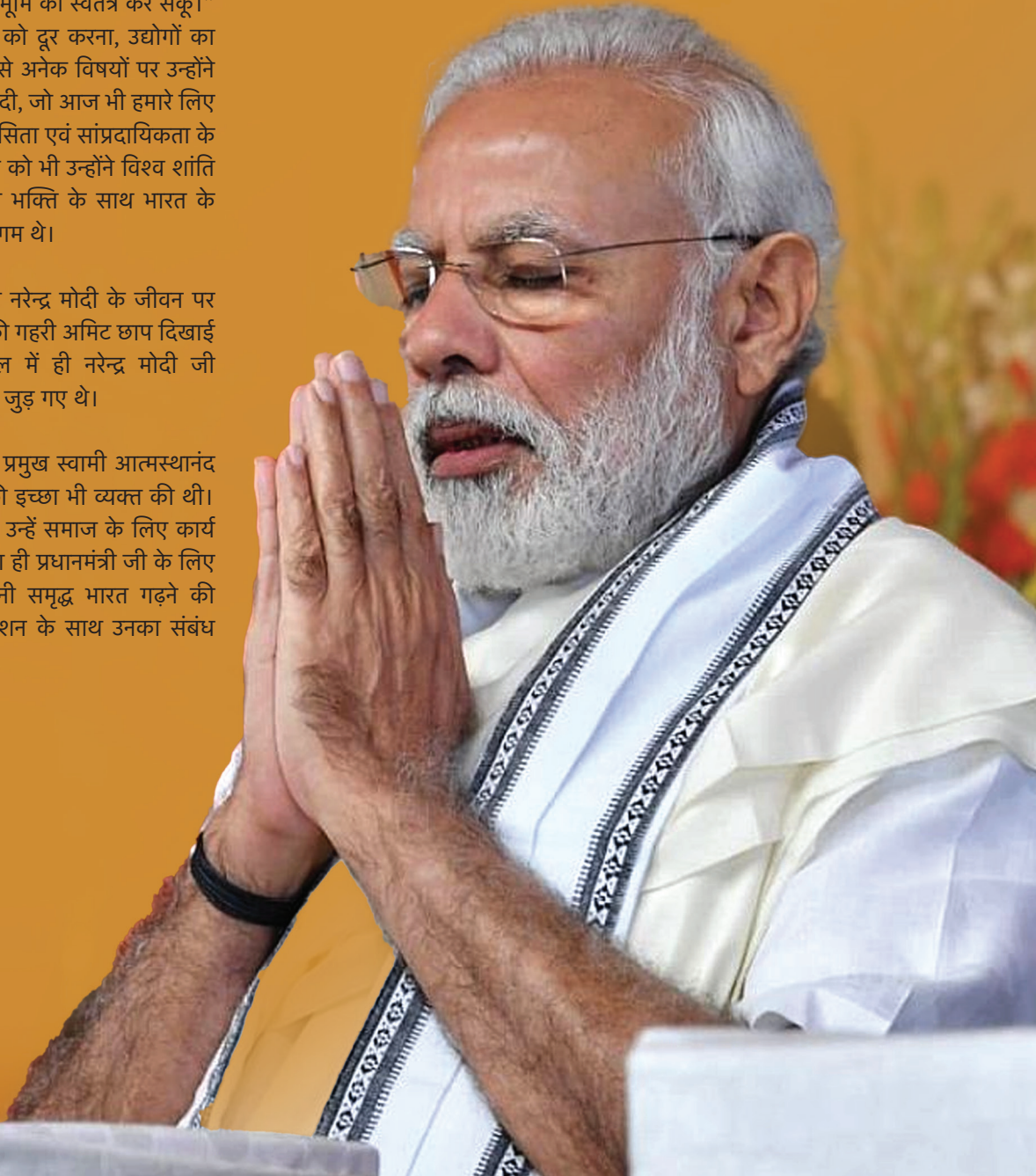
राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री
भाजपा

12 जनवरी, 1863 को कोलकाता के संभ्रांत परिवार विश्वनाथ दत्त एवं भुवनेश्वरी देवी के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। भगवान शिव की तपस्या के बाद जन्मे इस बालक को बचपन में नाम मिला नरेन्द्रनाथ दत्त। जिसको प्रेम से परिवार के लोग नरेन के नाम से बुलाते थे। संन्यास दीक्षा के बाद नरेन स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। 11 सितंबर, 1893 को शिकागो (अमेरिका) में आयोजित कार्यक्रम के ऐतिहासिक भाषण से यह संत संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। स्वामी जी का यह भाषण हिंदू धर्म की विशेषताओं एवं मान्यताओं को विश्व भर में पुनर्प्रतिष्ठित करने में सफल हुआ।

गुलामी के कालखंड में भारतीय समाज में स्वाभिमान जगाने का कार्य उनके द्वारा हुआ। उनके इस प्रयास का परिणाम हुआ कि स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय सेनानियों की प्रेरणा के केंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन की घटना का उल्लेख किया, “मैंने स्वामी विवेकानंद से शक्ति देने के लिए कहा ताकि मैं अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कर सकूँ।” अस्पृश्यता निवारण, अशिक्षा को दूर करना, उद्योगों का विकास एवं महिला उत्थान जैसे अनेक विषयों पर उन्होंने भारत के विकास की नई दृष्टि दी, जो आज भी हमारे लिए प्रेरक मार्गदर्शन है। भोग-विलासिता एवं सांप्रदायिकता के संघर्ष में फंसे वैश्विक समुदाय को भी उन्होंने विश्व शांति का मार्ग दिखाया। स्वामी जी भक्ति के साथ भारत के आधुनिक विकास के अद्भुत संगम थे।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की गहरी अमिट छाप दिखाई देती है। अपने विद्यार्थी काल में ही नरेन्द्र मोदी जी रामकृष्ण मिशन (राजकोट) से जुड़ गए थे।

राजकोट शाखा के तत्कालीन प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद जी से उन्होंने संन्यास दीक्षा की इच्छा भी व्यक्त की थी। स्वामी आत्मस्थानंद जी ने ही उन्हें समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। यह प्रेरणा ही प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब कल्याण एवं स्वाभिमानी समृद्ध भारत गढ़ने की प्रेरणा बन गई। रामकृष्ण मिशन के साथ उनका संबंध आज भी जीवंत बना है।



स्वामी विवेकानंद गुलामी की मानसिकता के संबंध में कहते हैं, “परतंत्रता रूपी इस अंधकार ने भारत के स्वाभिमान को ऐसा ग्रहण लगाया कि भारतवासी अपना आत्मविश्वास ही खो बैठे।” आत्महीनता का परिणाम यह हुआ कि हमको हमारे महापुरुष, इतिहास, ज्ञान, कला एवं संस्कृति सभी में दोष देखने की प्रवृत्ति एवं विदेशी नकल को आधुनिकता का पर्याय मान लिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने भाषण में 15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को विकसित भारत बनाने का

संकल्प दोहराया। अमृत काल की इस बेला में उन्होंने प्रत्येक भारतीय को पंच प्रण का पालन करने का आग्रह किया। जिसमें भारतीय समाज को सभी प्रकार की गुलामी छोड़ने का भी प्रण था। 22 जनवरी, 2024 को श्रीराम मंदिर में भगवान श्रीराम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इसी स्वाभिमान को जगाने के अनेक प्रयासों में से एक है।

स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य की लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य, राष्ट्र सेवा जैसे विषय शामिल हों। नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा एवं भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का संकल्प स्वामी जी के विचारों का शिक्षा में प्रकट रूप है।

स्वामी विवेकानंद जी गरीबों की पीड़ा को देखकर बहुत व्यथित थे। अमेरिका के वैभव से भारत की गरीबी की तुलना करते हुए वह रात्रि भर रोते रहे। इसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि ‘दरिद्र देवो भव’। स्वामी जी ने भारत की उन्नति का घोषणा पत्र ही जैसे लिखा हो, उन्होंने कहा, “इस देश को उठने दो गरीबों की झोपड़ी से, मल्लाह की नौकाओं से, लोहार की भट्टियों से, किसानों के खेत-खलिहानों से, मोचियों की झोपड़ी से, गिरिकन्दराओं से, यह देश तो वहीं बसता है।” प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस घोषणा पत्र को साकार रूप देना प्रारंभ किया। समाज के अलग-अलग वर्ग के गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की।

स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, प्रत्येक गांव को विद्युत आपूर्ति के लिए उजाला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन आदि अनेक योजनाएं गरीब उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित हुईं। 4 करोड़ से अधिक परिवार को आवास देना, 1 करोड़ 36 लाख युवाओं को कौशल विकास विभाग रोजगार उपलब्धि का माध्यम बना। 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह अन्न पहुंचाना, गरीब की रोटी की समस्या का समाधान है। गरीब की रोटी के विषय पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि “गरीब को पहले रोटी दो, तब गीता सुनाओ क्योंकि उसकी आवश्यकता रोटी है।”

समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे छोटे-छोटे शिल्पकार जिसको प्रधानमंत्री जी ने भारत का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा कहा। इसमें बड़ई, लोहार, सोनार, सुतार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, धोबी आदि श्रेणी के लोग आते हैं। ऐसे वर्ग के लिए

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 30 लाख परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सहायता मिलेगी।

देश में ठेला लगाकर एवं रेहड़ी पट्टी के माध्यम से बेचने वाले वेंडर जैसे लघु उद्योगों के माध्यम से जीवन-यापन करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराकर उसके घर में रोशनी पहुंचने का कार्य किया है।

शिकागो धर्म सभा के अवसर पर अपने भाषण में शिव महिमा स्रोत से एक मंत्र को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा था-

रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिल नानापथजुषां।
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।।

समस्त धर्मों में एक ही परमात्मा का दर्शन एवं सबका लक्ष्य एक ही गंतव्य है, यह भाव उन्होंने व्यक्त किया था। संपूर्ण विश्व में योग की प्रतिष्ठा, कोरोना में ‘जान भी जहान भी’ के आधार पर विश्व को सहायता, G-20 में ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ का आदर्श वाक्य यह स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रस्तुत विचारों का प्रकटीकरण है।

स्वामी विवेकानंद जी का यह आह्वान “उठो जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको” को नरेन्द्र मोदी जी ने अपने जीवन का आदर्श मान लिया है। बिना रुके, बिना थके यह कर्मयोद्धा उत्तिष्ठत भारत के लक्ष्य प्राप्ति में लगा है। हम सभी भारतवासी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपने कदम-ताल मिलाए एवं अमृत काल में भारत को समृद्ध, सुरक्षित, गौरवयुक्त, स्वाभिमानी भारत बनाकर विश्व का तमस हटाने का संकल्प ले। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 12 जनवरी, 1863 को कोलकाता के संप्रान्त परिवार विश्वनाथ दत्त एवं भुवनेश्वरी देवी के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। भगवान शिव की तपस्या के बाद जन्मे इस बालक को बचपन में नाम मिला नरेन्द्रनाथ दत्त। जिसको प्रेम से परिवार के लोग नरेन के नाम से बुलाते थे। संन्यास दीक्षा के बाद नरेन स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। 11 सितंबर, 1893 को शिकागो (अमेरिका) में आयोजित कार्यक्रम के ऐतिहासिक भाषण से यह संत संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। स्वामी जी का यह भाषण हिंदू धर्म की विशेषताओं एवं मान्यताओं को विश्व भर में पुनर्प्रतिष्ठित करने में सफल हुआ।

गुलामी के कालखंड में भारतीय समाज में स्वाभिमान जगाने का कार्य उनके द्वारा हुआ। उनके इस प्रयास का परिणाम हुआ कि स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय सेनानियों की प्रेरणा के केंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन की घटना का उल्लेख किया, “मैंने स्वामी विवेकानंद से शक्ति देने के लिए कहा ताकि मैं अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कर सकूँ।” अस्पृश्यता निवारण, अशिक्षा को दूर करना, उद्योगों का विकास एवं महिला उत्थान जैसे अनेक विषयों पर उन्होंने भारत के विकास की नई दृष्टि दी, जो आज भी हमारे लिए प्रेरक मार्गदर्शन है। भोग-विलासिता एवं सांप्रदायिकता के

संघर्ष में फंसे वैश्विक समुदाय को भी उन्होंने विश्व शांति का मार्ग दिखाया। स्वामी जी भक्ति के साथ भारत के आधुनिक विकास के अद्भुत संगम थे।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की गहरी अमिट छाप दिखाई देती है। अपने विद्यार्थी काल में ही नरेन्द्र मोदी जी रामकृष्ण मिशन (राजकोट) से जुड़ गए थे।

राजकोट शाखा के तत्कालीन प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद जी से उन्होंने संन्यास दीक्षा की इच्छा भी व्यक्त की थी। स्वामी आत्मस्थानंद जी ने ही उन्हें समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। यह प्रेरणा ही प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब कल्याण एवं स्वाभिमानी समृद्ध भारत गढ़ने की प्रेरणा बन गई। रामकृष्ण मिशन के साथ उनका संबंध आज भी जीवंत बना है।

स्वामी विवेकानंद गुलामी की मानसिकता के संबंध में कहते हैं, “परतंत्रता रूपी इस अंधकार ने भारत के स्वाभिमान को ऐसा ग्रहण लगाया कि भारतवासी अपना आत्मविश्वास ही खो बैठे।” आत्महीनता का परिणाम यह हुआ कि हमको हमारे महापुरुष, इतिहास, ज्ञान, कला एवं संस्कृति सभी में दोष देखने की प्रवृत्ति एवं विदेशी नकल को आधुनिकता का पर्याय मान लिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने भाषण में 15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को विकसित भारत बनाने का

संकल्प दोहराया। अमृत काल की इस बेला में उन्होंने प्रत्येक भारतीय को पंच प्रण का पालन करने का आग्रह किया। जिसमें भारतीय समाज को सभी प्रकार की गुलामी छोड़ने का भी प्रण था। 22 जनवरी, 2024 को श्रीराम मंदिर में भगवान श्रीराम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इसी स्वाभिमान को जगाने के अनेक प्रयासों में से एक है।

स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य की लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य, राष्ट्र सेवा जैसे विषय शामिल हों। नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा एवं भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का संकल्प स्वामी जी के विचारों का शिक्षा में प्रकट रूप है।

स्वामी विवेकानंद जी गरीबों की पीड़ा को देखकर बहुत व्यथित थे। अमेरिका के वैभव से भारत की गरीबी की तुलना करते हुए वह रात्रि भर रोते रहे। इसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि ‘दरिद्र देवो भव’। स्वामी जी ने भारत की उन्नति का घोषणा पत्र ही जैसे लिखा हो, उन्होंने कहा, “इस देश को उठने दो गरीबों की झोपड़ी से, मल्लाह की नौकाओं से, लोहार की भट्टियों से, किसानों के खेत-खलिहानों से, मोचियों की झोपड़ी से, गिरिकन्दराओं से, यह देश तो वहीं बसता है।” प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस घोषणा पत्र को साकार रूप देना प्रारंभ किया। समाज के

अलग-अलग वर्ग के गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की।

स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, प्रत्येक गांव को विद्युत आपूर्ति के लिए उजाला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन आदि अनेक योजनाएं गरीब उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित हुईं। 4 करोड़ से अधिक परिवार को आवास देना, 1 करोड़ 36 लाख युवाओं को कौशल विकास विभाग रोजगार उपलब्धि का माध्यम बना। 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह अन्न पहुंचाना, गरीब की रोटी की समस्या का समाधान है। गरीब की रोटी के विषय पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि “गरीब को पहले रोटी दो, तब गीता सुनाओ क्योंकि उसकी आवश्यकता रोटी है।”

समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे छोटे-छोटे शिल्पकार जिसको प्रधानमंत्री जी ने भारत का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा कहा। इसमें बड़ई, लोहार, सोनार, सुतार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, धोबी आदि श्रेणी के लोग आते हैं। ऐसे वर्ग के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 30 लाख परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सहायता मिलेगी।

देश में ठेला लगाकर एवं रेहड़ी पट्टी के माध्यम से बेचने वाले वेंडर जैसे लघु उद्योगों के माध्यम से जीवन-यापन करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराकर उसके घर में रोशनी पहुंचने का कार्य किया है।

शिकागो धर्म सभा के अवसर पर अपने भाषण में शिव महिमा स्त्रोत से एक मंत्र को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा था-

रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिल नानापथजुषां।
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।।

समस्त धर्मों में एक ही परमात्मा का दर्शन एवं सबका लक्ष्य एक ही गंतव्य है, यह भाव उन्होंने व्यक्त किया था। संपूर्ण विश्व में योग की प्रतिष्ठा, कोरोना में ‘जान भी जहान भी’ के आधार पर विश्व को सहायता, G-20 में ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ का आदर्श वाक्य यह स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रस्तुत विचारों का प्रकटीकरण है।

स्वामी विवेकानंद जी का यह आह्वान “उठो जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको” को नरेन्द्र मोदी जी ने अपने जीवन का आदर्श मान लिया है। बिना रुके, बिना थके यह कर्मयोद्धा उत्तिष्ठत भारत के लक्ष्य प्राप्ति में लगा है। हम सभी भारतवासी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपने कदम-ताल मिलाए एवं अमृत काल में भारत को समृद्ध, सुरक्षित, गौरवयुक्त, स्वाभिमानी भारत बनाकर विश्व का तमस हटाने का संकल्प ले। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

Strengthening the Fabric of Society: The Imperative of Modi's Third Term for Social Equity

Anup Saha

National Vice-President, BJYM and MLA, West Bengal

Prime Minister Shri Narendra Modi has marked a significant turning point for India, bringing to the fore a comprehensive agenda for social justice that transcends political rhetoric to become an "Article of Faith." The efforts to empower OBCs, Dalits, and tribals under Prime Minister Modi's leadership reflect a multi-faceted approach to social justice, targeting economic empowerment, social dignity, and political representation. By addressing historical inequalities and providing platforms for advancement, the government aims to create a more inclusive and equitable society.

However, the path towards full empowerment and equity is ongoing, requiring sustained commitment and action to ensure that all citizens have the opportunity to thrive. Through several initiatives, Modi's administration underscores its dedication to the upliftment of India's marginalized communities, reinforcing the principle of "Sabka Saath, Sabka Vikas" (Together with all, Development for all) at the heart of its governance philosophy.

At the heart of Modi's social justice agenda is the

unwavering belief that development must be inclusive and reach every citizen of the country, regardless of their socio-economic status. This principle is not just a policy but a guiding light for the BJP, as PM Modi himself has articulated. The Modi government has undertaken numerous initiatives aimed at ensuring equality and social justice, reaching the most marginalized and disadvantaged sections of society.

For the OBCs, the Modi government has made concerted efforts to ensure their representation and access to opportunities. The Modi government has extended 27% OBC reservation to all Sainik schools, Kendriya Vidyalayas, and JNVS, as a consequence of which over 14 lakh children stand to benefit. Similar advantages OBC students have in professional courses, including NEET, law courses, etc. Additionally, the establishment of the OBC Commission as a constitutional body has been a significant step towards addressing the grievances and issues faced by OBC communities, ensuring their concerns are heard and acted upon at the highest levels.



The empowerment of Dalits has been another cornerstone of Modi's social justice agenda. The government has launched numerous schemes aimed at improving the socio-economic status of Dalit communities. Initiatives like the Stand Up India scheme have encouraged entrepreneurship among Dalits, providing financial support and incentives to start their businesses. Furthermore, the government's push for the eradication of manual scavenging, a practice that disproportionately affects Dalits through legislative measures and rehabilitation programs, reflects a commitment to dignity and social justice for the community.

For India's tribal populations, the Modi government has focused on ensuring their rights and access to resources. The implementation of the Forest Rights Act, which recognizes the rights of tribal communities over forest land and resources, has been a crucial step in empowering these communities. Additionally, the government has emphasized education and healthcare access for tribals, with the establishment of Eklavya Model Residential Schools providing quality education to tribal children and the launch of health and wellness centres in tribal areas to improve healthcare access.

Ever since the passage of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, various positive measures were created for easy accessibility of persons with disability, like the right to live with family. Also, the same act has opened a new window of skill development and empowerment required for a person with a disability.

The introduction of groundbreaking policies such as the EWS reservation demonstrates a bold step towards economic inclusivity, ensuring that the economically weaker sections of society gain access to education and employment opportunities. Furthermore, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has revolutionized financial inclusion by opening bank accounts for millions of Indians, providing them with a gateway to economic empowerment and participation in the formal economy.

The commitment to social justice extends to healthcare through the Ayushman Bharat scheme,

which offers health coverage to millions of vulnerable families, illustrating a significant stride towards equity in health access. Additionally, the Swachh Bharat Mission has not only improved sanitation and public health but also enhanced the dignity and quality of life for countless Indians, showcasing the holistic approach of Modi's government towards social justice.

The Modi administration's efforts have been particularly impactful for the marginalized communities, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward classes. Initiatives aimed at their development, such as improved access to education, healthcare, and economic opportunities, reflect a commitment to breaking the chains of historical injustices and inequalities.

As India stands on the brink of transformative change, the need for a leader who can continue to steer the nation towards greater inclusivity and social justice is evident. Modi's vision for social justice, deeply rooted in the belief of "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas," has laid a strong foundation for a more equitable society. However, the journey is far from complete.

The advancements made in social justice under Modi's leadership underscore the critical necessity of a third term. It is not merely a continuation of governance but a pivotal moment to ensure that the ideals of equality, empowerment, and inclusion reach their zenith. The achievements to date represent significant milestones, yet the path ahead requires steadfast leadership to navigate the challenges and opportunities that lie in realizing the full potential of India's social justice agenda.

In essence, a third term for Modi is not just a political decision; it's a mandate for advancing a social justice agenda that has begun to reshape India's socio-economic landscape profoundly. The continuation of this leadership is essential for nurturing the seeds of inclusivity, empowerment, and equity that have been sown, ensuring that they grow into a robust framework of social justice for all Indians.

Harvesting Progress: Modi's Third Term for Agricultural Renaissance and Farmer Prosperity

Rohit Chahal National General Secretary, BJYM

Prime Minister Shri Narendra Modi's visionary leadership in transforming India's agricultural landscape presents a compelling case for his third term in office. Under his governance, the agricultural sector has seen unprecedented growth and modernization, thanks to a holistic approach that marries traditional practices with cutting-edge technology. Initiatives like the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme have directly benefited millions of farmers, providing them with crucial financial support. Furthermore, PM Modi's emphasis on sustainable farming, through the promotion of organic agriculture and water conservation techniques, has not only increased agricultural productivity but also addressed long-term environmental concerns. These efforts are complemented by policies aimed at enhancing farmers' incomes through improved market access, agro-processing, and value addition, laying the groundwork for a self-reliant and prosperous agricultural future.

Moreover, PM Modi's administration has effectively leveraged digital technology to revolutionize agriculture, making farming more efficient and profitable. The government's focus on agricultural education and research ensures that farmers are equipped with knowledge and tools to face future challenges. At the same time, initiatives like the Agriculture Export Policy aim to make India a global leader in agriculture. The holistic and multifaceted

approach to agricultural reform under Modi's leadership, including the emphasis on insurance and risk management, underscores a deep commitment to the welfare of the farming community.

Under PM Modi's leadership, India has embraced a blend of traditional and modern agricultural practices. The promotion of natural farming, alongside technological advancements like Soil Health Cards, drone technology for crop monitoring, and the use of solar power on farms, underscores a commitment to sustainable agriculture. These initiatives not only enhance farm productivity but also ensure environmental conservation. The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme, providing direct financial assistance to farmers, signifies a major step towards financial empowerment. This income support initiative helps farmers manage the costs associated with agriculture, ensuring financial security.

The Modi government's investment in rural infrastructure, such as roads, electrification, and irrigation projects, is pivotal. The development of Krishi Vigyan Kendras and the National Agriculture Market (e-NAM) further demonstrates a commitment to creating a robust agricultural infrastructure, facilitating easier access to markets and better prices for farmers' produce. Recognizing the challenges posed by climate change, the government has launched several schemes like the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) to promote water conservation and efficient irrigation practices. Such initiatives are aimed at making Indian agriculture more resilient to climate variability.



The government's focus on allied activities such as horticulture, dairy, fisheries, and beekeeping underlines a holistic approach to rural and agricultural development. Programs like the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) aim to harness the potential of these sectors to enhance farmers' incomes and ensure nutritional security. Modi's leadership in promoting millets, which was declared the International Year of Millets, and the development of an Institute of Millets Research showcases India's role in leading global food security efforts. Emphasizing millets highlights a shift towards more nutritious and environmentally sustainable food choices.

The push towards forming Farmer Producer Organizations (FPOs) and providing farmers with affordable credit through schemes like the Kisan Credit Card (KCC) scheme illustrates a strategy to empower farmers collectively. Such measures ensure that farmers can access financial services more easily and gain better bargaining power in the market. The Modi government has placed significant emphasis on agricultural education, research, and extension activities. By fostering a strong network of agricultural universities and research institutions, the government aims to equip farmers with innovative practices and technologies. This focus on education ensures that farmers are well informed about the latest agricultural methods, crop varieties, and pest management techniques, leading to increased productivity and sustainability. The push towards organic farming through the Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) represents a move towards healthier and more sustainable agricultural practices. By supporting the organic farming sector, the government is not only ensuring the health of the soil and ecosystems but also opening up new market opportunities for farmers, given the growing demand for organic products both domestically and internationally. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is a groundbreaking crop insurance scheme that mitigates the risk faced by farmers due to extreme weather events and natural calamities. This scheme ensures that farmers are not left vulnerable in the face of adversity, thereby securing their livelihoods and encouraging them to continue farming without

fear of financial ruin.

The government has also made efforts to boost the agro-processing sector and promote value addition through initiatives like the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY). By developing food processing infrastructure and facilitating the establishment of food parks, the government is enabling farmers to fetch better prices for their produce and reduce wastage, thereby increasing their income levels. The government's focus on digital agriculture, through initiatives like the Digital Agriculture Mission, aims to integrate technology in every aspect of farming. From precision agriculture using IoT devices to blockchain for supply chain transparency, these initiatives are setting the stage for a tech-savvy agricultural sector that can lead India towards achieving high efficiency and productivity.

The Agriculture Export Policy, aimed at doubling agricultural exports by 2022, reflects the government's ambition to make India a global agricultural powerhouse. By removing barriers to export and establishing stable trade policies, the government is opening up international markets for Indian farmers, thereby promoting economic growth and diversification. Recognizing the critical challenge of water scarcity, the government has launched the Jal Shakti Abhiyan and other water conservation initiatives to ensure water security for agriculture. These efforts focus on rainwater harvesting, the rejuvenation of water bodies, and the efficient use of water resources, ensuring that agriculture remains sustainable even in water-stressed regions.

The policies and initiatives undertaken by Prime Minister Shri Narendra Modi's government have laid a solid foundation for a transformative agricultural sector. These efforts not only aim at enhancing farm productivity and sustainability but also focus on improving the livelihoods of millions of farmers across the country. Given these accomplishments and the ongoing commitment to agricultural and rural development, PM Modi's argument for a third term is strongly supported by the progress and benefits realized by the farming community under his leadership.

A Trifecta of Triumph: Modi's Third Term as the Keystone of India's Defence Fortitude

Vaibhav Singh
National General Secretary,
BJYM



रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE
भारत सरकार



रक्षा उत्पादन विभाग
DEPARTMENT OF
DEFENCE PRODUCTION
GOVERNMENT OF INDIA

The transformative impact of Prime Minister Shri Narendra Modi's leadership on strengthening the defence and security of India is a narrative of strategic foresight, commitment to self-reliance, and a holistic approach to national security. Under his tenure, India has witnessed significant advancements in its defence capabilities, driven by a series of initiatives that underscore the government's resolve to protect its sovereignty while promoting peace and stability in the region. Under PM Modi's leadership, India has taken significant strides in fortifying its defence capabilities through unique initiatives and forward-thinking strategies that extend beyond conventional military modernization. These initiatives highlight the government's comprehensive approach to national security, leveraging technology, international partnerships, and policy reforms to ensure India's sovereignty and global standing.

Embracing Indigenous Defense Production

A cornerstone of PM Modi's defence strategy is the emphasis on indigenous defence production, encapsulated in the "Make in India" initiative. This vision has led to remarkable achievements such as the development of the Tejas fighter jets, the commissioning of INS Vikrant, India's first indigenously built aircraft carrier, and the advancement of the Akash missile system. These milestones not only signify India's growing self-reliance in defence manufacturing but also enhance its stature on the global stage as a defence exporter.

Strengthening Cyber and Space Security

Recognizing the evolving nature of warfare, Modi's government has prioritized the strengthening of India's cyber and space security. Initiatives like the establishment of the Defence Space Agency and the Defence Cyber Agency underline the strategic move towards protecting India's assets in space and cyberspace, crucial domains of contemporary warfare.

Modernizing Military Infrastructure

Under PM Modi's leadership, there has been a significant focus on modernizing military infrastructure and capabilities. The strategic border

roads, bridges and the push for digital and network-centric warfare are transforming India's military posture. The dedication to modernization is evident in the induction of cutting-edge platforms like the Rafale jets, which have significantly boosted the Air Force's combat capabilities.

Boosting International Defense Cooperation

PM Modi's tenure has seen a concerted effort to enhance international defence cooperation. Strategic partnerships with key global players have been strengthened, exemplified by the acquisition of advanced defence platforms and technology transfer agreements. These international collaborations not only bolster India's defence capabilities but also contribute to maintaining regional and global peace.

Commitment to Defense Reforms

The Modi government has introduced comprehensive defence reforms aimed at optimizing resource management and operational effectiveness. The creation of the post of the Chief of Defence Staff (CDS) and the push towards theaterization are aimed at ensuring better synergy and jointness among the Indian Armed Forces, reflecting a modern approach to defence planning and coordination.

Vision for a Self-Reliant Defense Sector

The vision of Atmanirbhar Bharat (Self-reliant India) has deeply influenced defence policies, with an increased focus on domestic research and development and the promotion of public and private sector participation in defence manufacturing. This self-reliance is a strategic move to reduce dependence on imports and to develop indigenous capabilities that cater to the specific requirements of the Indian armed forces.

Establishing Indigenous Defense Ecosystem

PM Modi's government has placed a strong emphasis on creating an indigenous defence ecosystem that encompasses not just manufacturing but also innovation and technology development. The launch of the Innovations for Defence Excellence (iDEX) initiative is a testament to this vision. iDEX aims to foster innovation and technology development in the defence and

aerospace sectors by engaging startups, MSMEs, and individual innovators. This initiative bridges the gap between the armed forces' technological needs and innovative solutions provided by the private sector, ensuring that India's defence forces are equipped with cutting-edge technologies.

Focus on Maritime Security

Recognizing the strategic importance of the Indian Ocean Region (IOR) and India's extensive coastline, the Modi government has prioritized maritime security. The Sagarmala project, aimed at enhancing the performance of the country's logistics sector, also indirectly bolsters India's maritime security by improving infrastructure and surveillance along the coastline. Additionally, the government has increased naval cooperation with countries in the IOR through joint exercises, port calls, and logistics agreements, enhancing maritime domain awareness and security.

Strategic Nuclear Submarine Development

In a significant boost to India's strategic deterrence capabilities, the Modi government has advanced the development of nuclear-powered submarines. The INS Arihant, India's first indigenous nuclear-powered ballistic missile submarine (SSBN), has been complemented by plans to develop more SSBNs and nuclear-powered attack submarines (SSNs). These platforms are crucial for ensuring India's second-strike capability and enhancing its strategic deterrence posture.

Defence Space Agency and Cybersecurity Initiatives
With the establishment of the Defence Space Agency (DSA) and the formulation of a dedicated space policy for defence, Modi's administration acknowledges the critical role of space in national security. The DSA's mandate to develop and operationalize space-based capabilities for the armed forces marks a significant leap in India's defence strategy. Concurrently, the launch of cybersecurity initiatives and the formulation of a national cybersecurity policy underscore the government's proactive stance on protecting India's cyber infrastructure and ensuring the security of critical information assets.

Enhancing Border Infrastructure

The Modi government has made unprecedented strides in enhancing border infrastructure, particularly along the Line of Actual Control (LAC) with China. The construction of roads, bridges, and advanced landing grounds in border areas not only facilitates rapid mobilization of troops but also reinforces India's claim over its border territories. This infrastructure development, coupled with the deployment of advanced surveillance systems, strengthens India's position in managing border disputes and ensuring territorial integrity.

Defence Procurement and Policy Reforms

Under PM Modi's leadership, India has seen significant reforms in defence procurement policies to promote transparency, efficiency, and self-reliance. The Defence Acquisition Procedure 2020 (DAP 2020), for instance, introduces measures to streamline procurement processes, encourage indigenization, and foster innovation through R&D. These policy reforms are designed to reduce procurement delays, minimize dependency on imports, and build a self-reliant defence manufacturing base.

Prime Minister Shri Narendra Modi's leadership has been instrumental in redefining India's defence and security paradigm. Through strategic initiatives aimed at modernization, self-reliance, and enhanced international cooperation, Modi has laid a robust foundation for India's defence sector. His vision for a secure, self-reliant India, bolstered by indigenous capabilities and strategic partnerships, underscores the imperative of his leadership for a third term. The continuation of these policies and the furtherance of these initiatives are crucial for ensuring India's security and asserting its position as a global defence player in the coming years.

Securing the Future: Why Modi's Third Term is Essential for India's Tech Ascendancy

PM Sai Prasad
National Treasurer, BJYM



In recent years, India has made significant strides in various fields under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, with science and technology being no exception. The government's proactive approach to promoting and integrating science and technology into the fabric of national development has paved the way for remarkable achievements and set the stage for a brighter future. Modi's vision for a technologically empowered India is not just about embracing the future; it's about creating it. His administration's policies and initiatives across various domains of science and technology—ranging from supercomputing and deep tech to artificial intelligence (AI) and biotechnology—have laid the foundation for a transformative leap into a future where technology drives growth, sustainability, and inclusivity. This expansion of the article delves deeper into these areas, underscoring why Modi's third term is pivotal for continuing this momentum.

Supercomputing: Powering India's Technological Sovereignty

The National Supercomputing Mission (NSM) is a testament to Modi's commitment to achieving technological sovereignty and enhancing research capabilities. Launched to build a vast network of supercomputers across the country, NSM aims to provide the computational power needed for advanced scientific research, weather prediction, space exploration, and AI. Under Modi's leadership, India has made significant progress in indigenous supercomputer development, exemplified by the launch of "Param Siddhi" – ranked among the world's top 500 most powerful non-distributed computer systems. This leap in supercomputing underlines the government's dedication to supporting high-end research that can drive innovation across sectors.

Revolutionizing Space Exploration

Under PM Modi's tenure, India has witnessed unprecedented advancements in space exploration, highlighted by ambitious missions that have not only propelled India into the global space arena but also instilled a sense of national pride and global recognition. Initiatives like the Mars Orbiter Mission, which positioned India as the first Asian nation to orbit Mars and the first in the world to do so on its maiden attempt, exemplify the Modi

government's vision. The forthcoming Gaganyaan mission, aiming to send Indian astronauts into space, underscores the administration's commitment to achieving new heights and harnessing space technology for national development.

Deep Tech: Navigating the Future

The Modi government's focus on deep tech, encompassing technologies like quantum computing, blockchain, and robotics, is preparing India for the next wave of technological revolution. By fostering a robust ecosystem for startups and research in deep tech, the administration is not only aiming for technological breakthroughs but is also ensuring that India remains at the forefront of solving complex global challenges. Initiatives like the Quantum-Enabled Science and Technology (QuEST) program highlight India's ambition to lead in quantum computing, promising breakthroughs in cryptography, material science, and drug discovery.

Artificial Intelligence: Shaping a Smart India

Artificial Intelligence (AI) is at the heart of Modi's vision for a "New India." The government's approach to AI is multi-faceted, aiming to leverage its potential for economic growth, social welfare, and governance. The National Strategy for Artificial Intelligence outlines a comprehensive plan to use AI for social empowerment, focusing on healthcare, education, agriculture, and smart cities. Projects like AI-based crop yield prediction models and AI-integrated health diagnostics are examples of how the Modi government is integrating AI to address critical societal issues, thereby transforming the lives of millions.

Biotechnology: Pioneering a Bio-Economy

Biotechnology is another sector receiving significant attention under Modi's leadership, given its potential to revolutionize healthcare, agriculture, and environmental sustainability. The Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC), under the Department of Biotechnology, has been instrumental in supporting research and innovation in biotech. The government's initiatives have led to remarkable advancements in vaccines, genomics, and agricultural biotechnology, propelling India towards its goal of becoming a

bio-economy powerhouse. The rapid development and deployment of the indigenous COVID-19 vaccine, Covaxin, underscore India's capabilities in biotechnology and vaccine development.

Promoting Science Education and Research

Recognizing the importance of nurturing scientific temper and innovation from the grassroots level, PM Modi's government has significantly bolstered science education and research. The establishment of new Indian Institutes of Technology (IITs), Indian Institutes of Information Technology (IIITs), and Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs) has expanded access to quality science and technology education, laying the groundwork for a knowledge-based economy. Furthermore, initiatives like the Atal Innovation Mission have been instrumental in fostering a culture of innovation among the youth, empowering them to contribute to India's technological advancements.

Spearheading Digital Transformation

The PM Modi administration's Digital India campaign has been a cornerstone of its science and technology policy, aimed at transforming the country into a digitally empowered society. The successful implementation of the Aadhaar project, the world's largest biometric ID system, and the Unified Payments Interface (UPI) has revolutionized digital payments, making financial transactions more accessible and secure for millions of Indians. These digital initiatives have facilitated not only ease of doing business but also significantly improved governance and service delivery.

Championing Renewable Energy and Environmental Sustainability

In the realm of science and technology, PM Modi's government has also taken significant steps

towards promoting renewable energy and environmental sustainability. The International Solar Alliance, initiated by India, exemplifies the country's leadership in global efforts to combat climate change through the adoption of solar energy. The government's ambitious target of achieving 175 GW of renewable energy capacity by 2022 underscores its commitment to reducing carbon emissions and fostering sustainable development.

Fostering International Collaborations

PM Modi's tenure has been marked by a proactive approach to forging international collaborations in science and technology. Strategic partnerships with global tech giants and countries have facilitated knowledge exchange, joint research, and innovation, thereby enhancing India's capabilities in cutting-edge technologies like artificial intelligence, quantum computing, and biotechnology. These international collaborations have not only bolstered India's scientific prowess but also positioned it as a significant player on the global stage.

The visionary leadership of Prime Minister Modi has been instrumental in propelling India's science and technology sector to new heights. Through strategic initiatives and policies, his government has fostered innovation, promoted scientific education and research, and leveraged technology for societal benefit. As India continues on its path towards becoming a global technology powerhouse, the achievements and progress made under PM Modi's administration make a compelling case for his third term. The continuation of this leadership is pivotal for India to realize its full potential in science and technology, ensuring the nation's progress and prosperity in the years to come.



Continuing the Legacy: Why Modi's Third Term is Crucial for India's Sporting Dreams

Aidan Singh Bhati
State Secretary, BJP Rajasthan

In recent years, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India has witnessed a paradigm shift in the realm of sports, marked by comprehensive policy reforms, significant investments in infrastructure, and a renewed emphasis on nurturing grassroots talent. The transformative initiatives undertaken during PM Modi's tenure not only underscore his commitment to elevating the status of sports in India but also present a compelling case for his leadership in steering the country's sports sector towards global recognition and success.

A Revolution from the Grassroots: The Khelo India Movement

At the heart of PM Modi's sports revolution is the Khelo India scheme, launched with the vision to scout, nurture, and bolster young sporting talent across the nation's length and breadth. This scheme has become a cornerstone for identifying and fostering budding athletes, providing them with platforms like the Khelo India Youth Games to showcase their skills. Through its inclusive approach, the scheme ensures that talent from underprivileged backgrounds, women, and persons with disabilities receive equal opportunities, thereby democratizing access to sports

opportunities and making sports a viable career option for the youth.

Supporting Elite Athletes: The Target Olympic Podium Scheme (TOPS)

Understanding the nuances of high-performance sports, the Modi government introduced the Target Olympic Podium Scheme (TOPS), a tailor-made support system for athletes with the potential to excel on the global stage. By providing financial assistance, access to world-class coaching, and state-of-the-art training facilities, TOPS has played a pivotal role in enhancing India's medal prospects at international competitions like the Olympics and Paralympics, culminating in historic wins that have propelled India onto the global sports stage.

Infrastructure: The Backbone of Sporting Excellence

Another critical aspect of PM Modi's sports policy is the emphasis on developing a robust sports infrastructure. The establishment and upgradation of stadiums, training centres, and sports academies across the country have ensured that athletes have



access to top-tier facilities. This focus on infrastructure development is crucial for nurturing talent and hosting international sporting events, thereby raising the profile of Indian sports globally.

Fostering a Culture of Fitness: The Fit India Movement

Beyond competitive sports, the Fit India Movement, launched by PM Modi, seeks to make fitness an integral part of every Indian's life. This initiative highlights the government's holistic approach to sports, emphasizing physical well-being as essential for national development. By promoting activities that encourage fitness, the movement aims to build a healthier nation.

Leveraging Technology: The National Sports Talent Search Portal

In a bid to bridge the gap between remote areas and the sports mainstream, the National Sports Talent Search Portal was introduced. This digital initiative simplifies the process for budding sportspersons to get recognized, ensuring that geographical and socio-economic barriers do not hinder talent discovery. This tech-driven approach reflects Modi's vision of using technology as an enabler in the sports domain.

Recognition and Empowerment of Athletes

Acknowledging the hard work and dedication of athletes, the Modi government has enhanced the prestige of national sports awards, ensuring timely recognition and better remuneration for their achievements. Moreover, by advocating for athletes' representation in sports governance, the government has empowered athletes to have a say in the decision-making processes, reflecting a shift towards more transparent and responsive sports administration.

A Paradigm Shift in Sports Governance

Under PM Modi's leadership, there has been a significant focus on reforming sports governance in India. By promoting transparency, accountability, and efficiency within sports organizations, the government has sought to create an environment where sporting talent can thrive without bureaucratic hurdles. This shift towards good governance is critical for sustaining long-term

growth and success in sports.

The Global Stage: Elevating India's International Sports Profile

The cumulative impact of these initiatives has been a marked improvement in India's performance and reputation on the international sports stage. Success stories from the Olympics, Paralympics, Commonwealth Games, and other prestigious competitions have not only brought laurels to the country but also inspired a new generation of athletes and sports enthusiasts.

In sum, Prime Minister Shri Narendra Modi's tenure has been characterized by an unprecedented focus on sports, marked by strategic policy interventions, investments in infrastructure, and a holistic approach to nurturing talent. Under his astute leadership, India has embarked on an unprecedented journey towards establishing itself as a formidable force in the global sports arena. The visionary initiatives and policies introduced by his government have not only rejuvenated the sports infrastructure across the nation but have also instilled a new sense of enthusiasm and professionalism among athletes and sports enthusiasts alike.

The government's focus on inclusivity and excellence in sports has not only opened new avenues for athletes but has also inspired millions of Indians to adopt a more active and healthy lifestyle. The transformative changes implemented under his leadership have not only elevated the status of sports in India but also laid a solid foundation for future success.

As India looks forward to sustaining this momentum and achieving greater heights in the world of sports, PM Modi's leadership and vision remain pivotal. The progress made thus far presents a compelling case for his third term, where the dream of establishing India as a global sports powerhouse can be realized, fulfilling the aspirations of countless athletes and bringing pride to the nation on the international stage. Prime Minister Modi's visionary leadership has undoubtedly laid a robust foundation for a brighter and more vibrant sporting future for India, making him a beacon of hope and inspiration for generations to come.

मोदी की गारंटी पर है देश को भरोसा

अजय धवले प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा,
मध्यप्रदेश व कॉर्पोरेट लॉयर



नरेंद्र मोदी जी 25 मई, 2024 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्ष पूर्ण कर लेंगे। इस एक दशक में हुए विकास कार्यों के आधार पर आज सबके मन में यह विश्वास है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अपने दो कार्यकाल में मोदी जी की सरकार ने आर्थिक नीति के मोर्चे पर अनगिनत साहसिक निर्णय लिए हैं। जिसकी वजह से भारत की गणना अब विश्व के अग्रिम और संभावना वाले देश के तौर पर की जा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में देखें तो वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दसवें स्थान पर थी। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृतकाल के दौर में प्रवेश कर चुका है, हम ग्लोबल इकोनॉमी में पांचवें स्थान पर आ गए हैं। भारत ने युनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा है और ये मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की बड़ी सफलता है। भारतीय राजनीति पर मोदी सरकार का प्रभाव बहुआयामी एवं महत्वपूर्ण है। मोदी जी की सरकार ने जनहितैषी नीति निर्माण और उनके सफल क्रियान्वयन का एक नया युग शुरू किया है। हालाँकि, सरकार के शुरुवाती दौर में पूर्ववर्ती सरकारों के समय से चली आ रही आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान कई नीतियों को समयानुक्रमिक बनाने के लिए एवं धारा के विपरीत जाकर देश की 140 करोड़ जनता के कल्याण को केंद्रबिंदु बनाने हेतु सरकार को आलोचनाओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, जो भारत जैसे विविध और तेजी से बदलते देश पर शासन करने की जटिलता को दर्शाता है। हम ने यह भी देखा है की समग्र विकास, कल्याण और आर्थिक सुधार पर सरकार के जोर ने राजनीतिक चर्चा और चुनाव परिणामों को आकार दिया है। एक ओर सरकार की नीतियों ने स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच में सुधार करने में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है वहीं सामाजिक-आर्थिक नीतियों ने भारत की विकास यात्रा में योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में आर्थिक विकास की बदौलत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके कारण देश आज आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसमें जी.एस.टी. लागू करने से हमारी कर व्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि के साथ ही व्यापारी और आम लोगों को भी सहूलियत हुई। सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिसके बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों में वृद्धि हुई। 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'पी.एल.आई. स्कीम', 'दीवालिया कानून', 'ईज आफ डूइंग बिजनेस', 'डिजिटलीकरण' जैसे सुधार कार्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल हैं। 'जनधन योजना' के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था से पूरा देश जुड़ गया है।

वर्ष 2014 तक मात्र 2.45 करोड़ बैंक खाते थे, लेकिन वित्तीय समावेश के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत 51 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इनमें 229,908.27 करोड़ रुपए जमा हैं। डिजिटलाइजेशन में आज विश्व का 40 प्रतिशत डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। मोबाइल का चिप कमी हम दूसरे देशों से आयात करते थे, आज हम इसके उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं।

पूर्ववर्ती सरकारें गरीबी हटाओ के नारे के साथ सिर्फ चुनाव ही जीतती

रही हैं। गरीबी के उत्थान और उनके कल्याण के लिए कांग्रेस सरकारों ने कभी गंभीरता के साथ कोई कार्यक्रम नहीं चलाए। यही वजह है कि कांग्रेस सरकारों के दौरान देश के करोड़ों लोग गरीबी और महंगाई से तरत रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का उल्लेख करते हुए बताया गया कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार के दौरान साल 2005-2006 में जहां 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, वहीं साल मोदी सरकार के कार्यकाल में 2021 तक ही गरीबी के आंकड़े घटकर 16% ही रह गए। पीएम मोदी के शत-प्रतिशत सैंचुरेशन और हर योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के विजन के चलते ही गरीबी सूचकांक में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

एक वक्त था, जब अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। खाने के लिए गेहूं से लेकर दवाओं और रक्षा के उपकरणों तक के लिए भारत दूसरे देशों पर आश्रित था। समय के साथ-साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा था और वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने आधिकारिक रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। महत्वपूर्ण यह है की यह अभियान ऐसे दौर में शुरू किया गया था, जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी की चपेट में था। तब भारत ने अपनी जीडीपी का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज केवल कोविड-19 से लड़ने के लिए लगा दिया।

इसी का परिणाम रहा कि संकटकाल में भारत ने अपने लिए तो संसाधन तैयार किए ही, विश्व के कई देशों को पीपीई किट से लेकर चिकित्सा के तमाम उपकरण और दवाइयां भेजकर मदद की। भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए स्वदेशी कोविड वैक्सीन बनाई जिसका लाभ देशवासियों के साथ-साथ अनेको देशों को हुआ। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान में अर्थव्यवस्था, ढांचागत संसाधन जैसे कई और पहलुओं को जोड़ा गया। देश में सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की पहल हुई। आसान और स्पष्ट कानून बनाए गए, कौशल विकास पर ध्यान देकर कुशल मानव संसाधन तैयार किए गए। आर्थिक प्रणाली को मजबूती दी गई।

मोदी सरकार GYAN- गरीब युवा अन्नदाता और नारीशक्ति के सशक्तीकरण से राष्ट्रनिर्माण को समर्पित है। GYAN ही देश की ताकत, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास है। GYAN भारत की वह शक्ति है जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाएगी। पिछले एक दशक में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन और विकास के ठोस प्रयासों का ही प्रतिफल है कि जन आशीर्वाद भाजपा के साथ है और प्रत्येक नागरिक मोदी की गारंटी में अपनी आस्था दिखा रहा है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पास नीति भी है, नेतृत्व भी है और नियति भी है जिससे यह निश्चित हो गया है की देश में फिर एक बार मोदी सरकार आने जा रही है।



A Greener Tomorrow: Why Modi's Environmental Legacy Deserves a Third Term

Kunal Tilak

Member Editorial Board, BJYM Magazine
and Vice-President, BJYM Maharashtra

In an era where the battle against climate change has become the defining challenge of our times, one leader's visionary quest for a greener future has captured the imagination of a nation and beyond. Prime Minister Shri Narendra Modi, with his charismatic leadership and an unwavering commitment to sustainability, is steering India towards an environmental renaissance. Under his guidance, India is not just navigating the green path but is doing so with an ambition and scale that is unparalleled. From the sun-kissed solar farms of Gujarat to the lush forests of the Northeast, PM Modi's green agenda is weaving a tapestry of eco-conscious initiatives across the vast and diverse canvas of India.

At the heart of PM Modi's environmental strategy is a profound understanding that true progress must

be harmonious with nature. This philosophy has translated into a series of transformative policies and initiatives, positioning India as a pivotal player on the global stage of climate action. Whether it's championing the International Solar Alliance or setting ambitious targets for renewable energy, PM Modi's India is debunking the myth that economic growth and environmental stewardship cannot go hand in hand. Through a blend of strategic diplomacy, national policy reforms, and a clarion call for community participation, PM Modi's leadership is a beacon of hope for a sustainable future, inspiring nations and individuals alike to rise to the challenges of our times.

Leadership in Global Climate Action

Under PM Modi's leadership, India has positioned itself as a pivotal player in global climate diplomacy, notably through its proactive roles in the G20, COP21, and the launch of the International Solar Alliance. This international leadership underscores PM Modi's commitment to leveraging India's growing influence to foster global cooperation on climate change, emphasizing the importance of technology transfer and financial support to the Global South for sustainable development.

National Policies for Climate Mitigation

India's National Action Plan on Climate Change (NAPCC), featuring key missions like the National Solar Mission and the National Mission for Enhanced Energy Efficiency, showcases PM Modi's strategy to integrate sustainable development with economic growth objectives. This holistic approach is aimed at reducing carbon emissions, enhancing renewable energy capacity, and promoting energy efficiency across various sectors, thereby contributing significantly to India's climate mitigation efforts.

Focus on Renewable Energy

PM Modi's ambitious targets for renewable energy, aiming to achieve 450 GW by 2030, highlight a strategic shift towards reducing dependence on fossil fuels and promoting sustainable energy sources. The government's investment in solar and wind energy, coupled with initiatives like the National Hydrogen Mission, illustrates a

forward-thinking approach to harnessing India's vast renewable energy potential.

Enhancing Environmental Sustainability

The implementation of the Green India Mission and initiatives like Mission LiFE (Lifestyle for Environment) reflects PM Modi's vision of embedding environmental sustainability into the fabric of Indian society. These initiatives aim to increase forest cover, promote biodiversity conservation, and encourage sustainable lifestyles among citizens, demonstrating a comprehensive approach to environmental stewardship.

Water Conservation and Pollution Control

Efforts like the Jal Jeevan Mission and the Namami Gange programme underline PM Modi's commitment to addressing India's water challenges. These initiatives focus on providing clean drinking water, rejuvenating India's rivers, and improving water resource management, which are critical for the country's sustainable development.

Advocacy for Clean and Green Mobility

The push towards electric vehicles (EVs) through policies like the FAME India scheme and the promotion of non-fossil fuel-based transportation options are part of PM Modi's strategy to reduce air pollution and greenhouse gas emissions. By fostering a conducive environment for the adoption of EVs, PM Modi is steering India towards a cleaner, greener future in mobility. By providing incentives for the purchase and manufacture of EVs, PM Modi's policies are paving the way for a significant shift towards cleaner, more sustainable modes of transportation.

Fostering Green Governance

Under PM Modi's administration, green governance has become a cornerstone of policy and practice. Initiatives like the Green Credit Programme, which incentivizes environmentally friendly actions by individuals and organizations, reflect an innovative approach to promoting sustainable practices. This programme is part of a broader strategy to embed environmental consciousness into the fabric of governance, ensuring that sustainability is integral to India's developmental agenda.

Innovating for a Greener Agriculture

Recognizing the critical role of agriculture in India's economy and environmental health, PM Modi's government has introduced groundbreaking initiatives to promote sustainable agriculture. The emphasis on nano-fertilizers and the development of a policy framework to regulate and encourage the use of nano-agriproducts (NAPs) demonstrate an innovative approach to enhancing agricultural productivity while minimizing environmental impact.

Championing Nano-Sustainability

Under PM Modi's leadership, India has embraced the potential of nanotechnology to address environmental challenges, showcasing an innovative approach to sustainability. The launch of the National Nano Mission underscores India's commitment to leveraging cutting-edge science for environmental conservation, focusing on nano-biotechnology applications in safe drinking water, material development, and sensor innovation. This initiative highlights the government's forward-thinking strategy to harness nanotechnology for sustainable development, ensuring that India remains at the forefront of scientific advancements aimed at preserving the environment.

Engaging the Community and Youth

PM Modi's leadership emphasizes the importance of community and youth engagement in India's green transition. Initiatives that foster public participation and awareness, such as the Swachh Bharat Mission and eco-friendly movements, are vital for cultivating a culture of environmental consciousness among Indian citizens.

In conclusion, PM Narendra Modi's third term is pivotal for advancing India's green and sustainable agenda. Through a blend of international leadership, national policy initiatives, and community engagement, PM Modi's vision for a sustainable India aligns with global environmental goals and the country's developmental aspirations. His continued leadership is essential for steering India towards achieving its ambitious environmental and climate targets, thus making a significant contribution to global sustainability efforts.

Sarvōpakāranīti: Modi-fying Bharat, against Exclusivism

**Dr. Mrityunjay Guha
Majumdar**

Assistant Professor in
Quantum Technology, UPES
and Editorial Board Member
of the BJYM Magazine

"Sabka Saath, Sabka Vikaas" is the slogan that has not only captivated masses across Bharat but has been instantiated in policies and programmes across the nation. While the Western media is still as preoccupied as ever with projecting the NDA government as parochial and regressive, the Modi sarkar has opted for actions over rhetoric to silence its critics. The Bharatiya Janata Party was established in 1980 as a 'party with a difference'. With a stalwart like Shri Atal Bihar Vajpayee as its first president, the party found its mark in the Indian political space, premised on the natural cosmopolitanism that our Bharatiya civilizational ethos



endows us with. The party has moved from 2 seats in the 8th Lok Sabha to 303 seats in the 17th Lok Sabha, and all signs are pointing towards 'Teesri Baar Modi Sarkaar'. How has this happened?

The answer is simple. It has acted as a party by the Bharatiya, of the Bharatiya and for the Bharatiya. It has worked, as a government must, against entrenched corruption, inefficiency, and inter-generational points of conflict, all the while promoting comprehensive development. It has had the courage and the conviction to carry through with pathbreaking policies such as the abrogation of Article 370 for safeguarding Bharat's territorial integrity and the passing of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam – the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act – for women's reservation in the Lok Sabha and state legislatures.

Most importantly, what the Modi government has done is a systematic and focused dismantling of exclusivism and the tendency of other-ing within the country. Exclusivism is not seen just in the theological space but also in selective development based on the tendency of other-ing by the administrators of a nation. It is this historical malpractice that has been stood against by this government, and for this, Bharat is all the better! Infrastructure as an Enabler of Access

The development of infrastructure in the country has been undertaken at an unprecedented scale. Inclusive growth is being looked at as an integral part of Bharat's progress. For instance, the northeast has been a region where successive Congress governments, right from the times of Nehru, have harnessed the resources without necessarily giving a proportionate benefit to the people of the region. The resentment with the exclusivist and alienating policies of the central government under successive Congress regimes led to the birth of various youth agitation movements in the North-East, such as the All Assam Students' Union, the All Bodo Students' Union and the Naga Students' Federation. Some of these had members who went on to form insurgent groups, such as the ULFA in Assam.

The story is rapidly changing now. Prime Minister

Narendra Modi's recent unveiling of development projects worth ₹17,500 crore in Assam in 2024 emphasizes the government's dedication to improving the region's infrastructure and economy. These initiatives cover various sectors, including healthcare, oil and gas, railways, and housing, showcasing a multifaceted approach to regional development. Besides the North-East, the government's focus on enhanced access for tourism in the Himalayan states has been noteworthy, such as with the Kiratpur to Nerchowk four-lane section of the NH-21 that falls on the Chandigarh-Manali stretch. There has been stellar work undertaken under the leadership of Shri Nitin Gadkari (Union Minister for Road Transport and Highways) in roadways across the country, including in Jammu and Kashmir, for which he recently announced allocation of ₹2,093.92 crore for widening two National Highways and a ropeway.

Railways, too, have found a new role as the proverbial thread to sew together disparate corners of the nation. Under the Modi government, railways infrastructure is being restructured and re-envisioned to secure a robust arterial mode of exchange of people and goods. Recently, the Prime Minister inaugurated around 2,000 railway infrastructure projects that encompass the revamping of stations, construction of underpasses and over-bridges, as well as establishing trusted modes of assessment and repair of tracks worth ₹41,000 crore across India.

Today, the most remote parts of the country are being included on the literal as well as proverbial map of Bharat, as a nation and as a truth. Even in densely populated states such as Uttar Pradesh, even a decade back, the environment was not conducive to infrastructure development, investments, and jobs. But now that has changed, not only with the surge in spiritual and eco-tourism but also in areas critical for sustainable development like renewable energy and sustainable food processing techniques, as seen in the recent inauguration of over 14,000 projects worth ₹10 lakh crore in Uttar Pradesh.

Even with the electrification of railway routes Raninagar Jalpaiguri-Haldibari, Siliguri-Aluabari

section via Bagdogra, Eklakhi-Balurghat, Siliguri-Sivok-Alipurduar Junction-Samuktala section and Barsoi-Radhikapur sections in northern Bengal (in a significant ₹4500 crore infrastructure push in the state of West Bengal) is also directed at promoting sustainable development and access for the people of Poshchimbongo as well as the North-East.

Uniformity and Dharmic Outlook

In recent decades, Bharat's 'unity in diversity' had been fast going from the underlying premise of the nation to a misnomer for safekeeping regressive practices under the garb of secularism. Tolerance is an important aspect of any humanitarian or social model. However, tolerance towards the parochial is worse than intolerance. Under the Modi government, there has been a movement towards truly secularising Bharat and not appeasing any cross-section of society to receive validation points and kudos from international commentators.

The first hit against exclusivism and parochialism by the Modi government was over Triple Talaq in 2019. Triple Talaq was the absurd way in which a male could divorce his wife by simply saying 'Talaq' thrice – in some cases, even over WhatsApp text! After the Supreme Court of India ruled against the practice, the Indian parliament declared it illegal and unconstitutional, thereby showing the new-found conviction of the Bharatiya leadership to stand up against regressive other-ing of a woman often based on the whims and fancies of her usually estranged husband.

The Citizenship Amendment Act (CAA) was another landmark policy that was promulgated to safeguard the interests of the minorities who are persecuted in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Historically, all these lands had been part of the Bharatiya civilizational fold. We hear of the Puranic tales of Gandhara, Matsya, and Madra kingdoms in current-day Pakistan and Afghanistan, as well as those from Anga and Vanga, which comprise lands that today fall in Bangladesh. Over time, violent exclusivism, brought to these lands on the tip of a sword, led to instances of dehumanization or conversion of large sections of the population in these lands. After centuries, Bharat has taken a

stand to safeguard the interests of those who fell victim to this scheme of things and continue to suffer at the hands of iconoclasts and exclusivists in these lands.

The other major step that the Uttarakhand BJP government has taken, and to which end there has been significant discussion and movements within the national circles, as well, is that of the Uniform Civil Code. Within the not-fully-qualified idea of secularism lay the seed that allowed for exclusivist tendencies and regressive practices to thrive as well as, in some circumstances, obtain undue advantages with respect to the demographic dimensions of the nation or even the political dividends thereof. Testamentary succession rights (as discussed in the Hadith), coparcenary rights for disposal of ancestral property (as discussed in the Hindu Succession Act), as well as stances against polygamy have all been part of the deliberation on how we can think of a progressive, uniformly administered Bharat, which doesn't lay excessive emphasis on ideas and constructs, across all religions and belief-systems, that may have had relevance in a certain context but may not now anymore. Prime Minister Shri Narendra Modi has time and again highlighted that the country could not run with the dual system of "separate laws for separate communities".

The reason Bharat needs a Modi Sarkaar for the third time is that it needs the willpower displayed by Shri Narendra Modi to stand against the exclusivist corruption of the social fabric of Bharat over the past millennium and thereby reclaim its Dharmic cosmopolitanism, which is more secular than what modern Western proponents of secularism often posit. I would like to end my meditation with what I feel will be a justifiable election slogan for the General Elections 2024:

राष्ट्रीयव्याकार, सहिष्णुसर्वोपकार

Translation: National transformation with tolerant beneficence for all

Namo 3.0 & Collective Intentionality

Yuvraj Singh
Vice-President, BJYM
Jammu and Kashmir



Collective intentionality in sociology refers to the ability to jointly direct the power of our minds to a common objective in order to achieve it. This ability is uniquely human, wherein individuals come together, cooperate and engage in a joint action even though it might not serve their immediate interests. In Amritkaal 2047, India will celebrate its 100 years of independence, and our Prime Minister, Shri Narendra Modi's vision is to make India "Viksit Bharat" by the year 2047. This mammoth task is not just the responsibility of our government; this is where common intentionality and collective effort from society are required. Every citizen of India has to realize that they are partners in this enterprise and have a particular role to play in it, but they have to voluntarily take up this responsibility collectively because responsibility cannot exist where agency, intentionality, freedom and autonomy have been abdicated.

The last 10 years of governance under the Modi government is a model that is indeed based on Rama-Rajya and is deeply fixated on the values mentioned in the Arthashastra concerning good governance, able leadership, strong economy, and defence, along with people-centric administration. From day one, the Modi government has focused its governance on dignity, welfare, empowerment, and the upliftment of the poor. All the flagship policies of the Modi government, such as PMAY, Jan Dhan Yojana, Jal Jeevan Mission, Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, Pradhan Mantri Kissan Maan Dhaa Yojana etc., are oriented towards the welfare of poor and marginalized, through which the government has successfully brought 25 crore people above the poverty line.

India has gone from being in the Fragile 5 to being in the Top 5. India, in the last 10 years, has witnessed massive economic growth, which includes stimulating existing businesses through economic reforms or facilitating FDI through ease of doing business. It has brought about a paradigm shift in the youth's outlook from being job seekers to job creators, inspiring them to build value-creating businesses by building the Start-Up culture and incubating it through start-up-friendly policies.

Our country, being the 4th largest military spender, has heavily relied on other nations to import defence systems and technologies due to a lack of conducive ecosystems and policies within our country. Today, we have a defence export value of more than 16,000 crores, compared to a mere 1521 crores in 2016-17, with around 200 defence-related start-ups engaged in creating indigenous defence technologies and weaponry, revolutionizing National Security, economic prosperity and taking the country a step closer to Atmanirbhar (self-reliance) in defence.

The pursuit of self-reliance, or Atmanirbhar, has also been reflected in India's foreign policy, enhancing India's influence within global politics. In the last decade, PM Modi has developed and nurtured deep relations with the global community, but with the vision of being assertive about India's interests. This shift in our foreign policy has not only solidified India's stance with firm opinions and ideas but also demonstrated strong convictions and strategies to achieve them, prompting a shift in the global community's perspective toward India.

As of today, it is unequivocally apparent that the return of the Modi Government, i.e. NaMo 3.0, is necessary and inevitable, and the achievements discussed above adequately justify the re-election of the incumbent government. But this time, our Prime Minister does not just require our votes; the slogan "Sabka Sath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas aur Sabka Prayas" underlines the fact that just exercising our right to vote is not enough to achieve the vision of Viksit Bharat. "Sabka Prayas" emphasizes the importance of collective intentionality, collective responsibility, and collective effort that are demanded of our society. As we know, society is nothing over and above its members. It has no will but the will of its members, no activity but the activity of its members, no responsibility but the responsibility of its members.

Advancing with Modi: A Third Term for India's Unprecedented Journey

Varada Bhaskar Teja
Professional Group Member - BJYM PRT

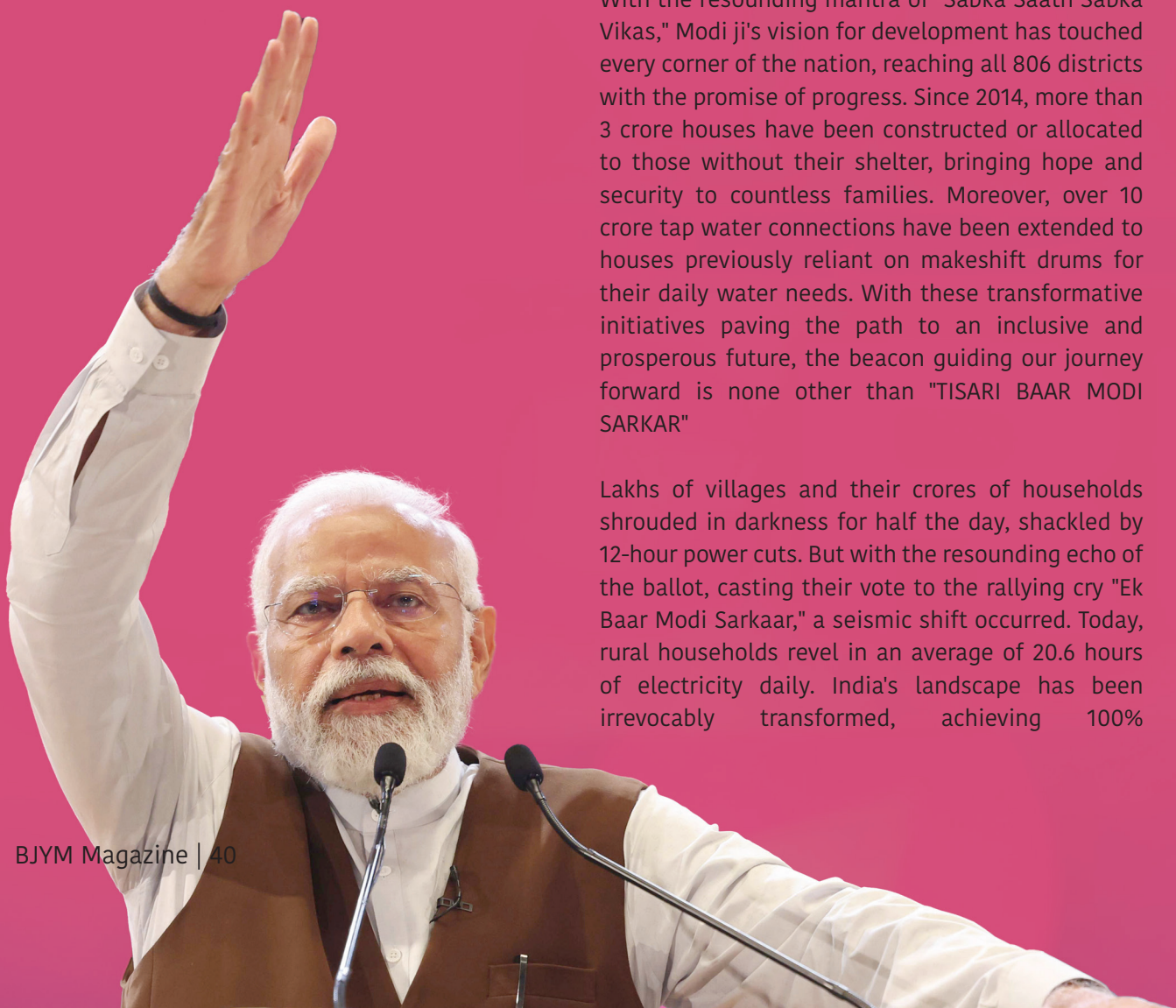
In the annals of future history, the remarkable ascent of India from 2014 will have its mark. It will recount a time when the nation grappled with financial scandals, the spectre of civilization's decline, and a tepid response to terror from hostile nations before 2014. Amidst this chaos emerged a rallying cry: "Ek Baar Modi Sarkar." This slogan, born of a populace yearning for change, propelled a leader with a proven track record of transformation in his native state of Gujarat to the highest echelons of power. The reforms and initiatives initiated since 2014 began to bear fruit, heralding a new era of growth and development.

ROTI, KAPADA, MAKAAAN to SADAK, BIJILI, PANI

In a monumental endeavour unparalleled on the global stage, the Modi government has orchestrated one of the largest food distribution programs, providing sustenance to 80 crore impoverished individuals through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Amidst the darkest of nights, the needy no longer fear the pangs of hunger as the beacon of hope emanates from this initiative. For every impoverished Indian, the bedrock of their food security lies in the unwavering promise of "TISARI BAAR MODI SARKAR"

With the resounding mantra of "Sabka Saath Sabka Vikas," Modi ji's vision for development has touched every corner of the nation, reaching all 806 districts with the promise of progress. Since 2014, more than 3 crore houses have been constructed or allocated to those without their shelter, bringing hope and security to countless families. Moreover, over 10 crore tap water connections have been extended to houses previously reliant on makeshift drums for their daily water needs. With these transformative initiatives paving the path to an inclusive and prosperous future, the beacon guiding our journey forward is none other than "TISARI BAAR MODI SARKAR"

Lakhs of villages and their crores of households shrouded in darkness for half the day, shackled by 12-hour power cuts. But with the resounding echo of the ballot, casting their vote to the rallying cry "Ek Baar Modi Sarkaar," a seismic shift occurred. Today, rural households revel in an average of 20.6 hours of electricity daily. India's landscape has been irrevocably transformed, achieving 100%



electrification during the last 10 years. Yet, the journey doesn't end here. As we embark upon the next phase, producing electricity at homes with solar rooftop panels and bestowing them with free electricity through PM Surya Ghar: Muft Bijili Yojana, we march boldly forward. With the advent of PM Ujjwala Yojana, the act of cooking over an open flame is but a distant memory. LPG connections, once a luxury, have surged from 14.5 crore in 2014 to a staggering 31.4 crore by August 2023, heralding a new era of safety, convenience, and progress for households across the nation. In this quest to banish the darkness in the home permanently with a bonfire, the fuel igniting the path forward is none other than "TISARI BAAR MODI SARKAR".

As gazes fix upon the vast expanse of highways and expressways that stretch into the horizon, pupils dilate in wonder, reflecting the infinite possibilities that lie ahead. Gone are the days of stagnation, where bureaucratic hurdles halted the progress of vital infrastructure projects. Over the past decade, a staggering 54,900 kilometres of national highways have been constructed, dwarfing the meagre 25,700 kilometres achieved between 2004 and 2014. The path to further expansion of the expressway network into the heartlands of our nation lies in the resolute leadership of "TISARI BAAR MODI SARKAR"

The Prime Minister's firsthand experiences on public transport from 1975 to 2002, spanning tens of states and hundreds of districts, fueled his commitment to ensuring world-class infrastructure for every traveller. Under his leadership, the number of airports skyrocketed from 74 to 149 over the past decade, propelled by initiatives like UDAAN. Additionally, the introduction of over 50 state-of-the-art Vande Bharat trains within three years eclipses the mere 26 Shatabdi trains operational since their launch in 1988, marking a quantum leap forward in rail connectivity and passenger comfort. To witness the seamless operation of Vande Sleeper, Vande Metro, and Vande Bharat on every route, reaching every railway station, the indispensable requirement is "TISARI BAAR MODI SARKAR"

PADHAI & NAUKARI

Before the dawn of 2014, the discourse surrounding startups remained confined to the hushed tones of coffee shop conversations. Yet, with the resolute initiatives and unwavering support of the MODI Sarkar, startups found new grounds for growth within the corridors of business parks. A revolution was sparked, where the dreams of Young India to build and innovate transformed into tangible realities. Witness the staggering ascent: from a mere 350 DPIIT startups in 2014 to a staggering 1,17,257 by December 31, 2023. As these startups stand poised on the brink of greatness, yearning to transform into unicorns, the clarion call resounds louder than ever: "TISARI BAAR MODI SARKAR"

Tryst with the history- Soul of Bharat:

The construction of Ram Mandir represented a monumental leap towards India's cultural freedom. Not long ago, in 2016, discussions about the true essence of our civilization hardly had any space at literature festivals. Instead, the stages were dominated by individuals viewing our history through a Western lens, employing foreign templates and frameworks. Today, the landscape has drastically shifted, giving voice to Indic perspectives. The Prime Minister spearheaded various initiatives to decolonize the Indian psyche, including the repeal of 1500 colonial-era laws, the adoption of Indian naval ranks, and the implementation of the National Education Policy. To foster the environment for the development of original Indic ideologies, the necessity is "TISARI BAAR MODI SARKAR"

Every corner of India shall resonate with the resounding rhythm "Tisari Baar Modi Sakaar" in the festival of democracy of 2024 to build a nation that is

Politically Strong! Socially Empowered!
Economically Prosperous!

Technically innovative! Thoughtfully initiative!
Culturally Composed!

Eternally Excellent!

Tisri Baar Modi Sarkar: A Mandate for India's Continued Resurgence

Ronisha Datta

State Executive Member,
BJYM Assam Pradesh

The year 2014 witnessed the historic victory of the Bharatiya Janata Party (BJP) in the Indian general elections. With a clear majority, Prime Minister Shri Narendra Modi embarked on his journey of transforming Bharat. The 2019 elections further solidified the Modi government's position in Indian politics. In these two terms, PM Modi continued to strengthen the foundations of development and change, addressed the challenges, and reshaped the country's social, economic, and political environment. One of the key factors behind the Modi government's success is its structured approach to strengthening the country's main pillars - national security, cultural revival, infrastructure, and economy.

In the last decade, it seems that Bharat has adopted the policy that the best form of defence is offence. The new India does not tolerate hostile actions in any form that undermines national security. It was solidified with the Uri surgical strike and the Balakot airstrike, which was an assurance to the people of the country. The abrogation of Article 370 brought in a steep decline in the terrorist incidents in Kashmir. A total of 7,217 terrorist incidents took place in Kashmir from 2004-2014. But, in the last 10 years, from 2014 till now, only 2197 terrorist incidents have taken place. In a similar pattern, the communal riots in states like Uttar Pradesh and Assam have also declined due to the reforms in law and order. Foreign policy prioritizes the welfare of its people and does not allow anyone to bully us



into following their demands. This proactive and dynamic foreign policy focuses on forming relevant ties with key partners and neighbouring countries but also strategically answers back to hindrances caused by others. These efforts have raised our country's profile on the global forum.

PM Modi has also worked relentlessly for the cultural revival of Bharat. He has taught us to take pride in our own culture by growing out of the mindset that we are inferior to others. He has placed Yoga on the global stage and has given its intellectual ownership to Bharat. Many restoration and development projects like the Somnath Mandir, Maa Sharda Mandir, Kedarnath Mandir, Ujjain Corridor, Kashi-Vishwanath Corridor, Vindhyachal Dham Corridor, Badrinath Dham Corridor, have commenced the spiritual revival along with the enhancement of the economic potential of the country.

The government has launched several social welfare schemes that aim to break caste barriers and improve the quality of living of the poor and marginalized. The backward classes have representation at both local levels as well as at the upper levels of the administrative system. Schemes like Ujjwala Yojana, Mudra Yojana, JAM Trinity, etc., are targeted welfare programs to include all castes in the political, social, and economic mainstream. The construction of toilets and water supply, along with the development of internet infrastructure in villages, have led to the development of rural areas. PM Modi's message of 'Sabka Saath, Sabka Vikas' (Collective Effort, Inclusive Growth) has come across loud and clear as it has resonated with voters, especially with marginalized communities who feel empowered now.

Bharat has witnessed a digital revolution, with initiatives like Digital India and the Aadhaar biometric ID system. These initiatives have helped improve access to services, reduce corruption, and promote digital literacy across the country. One of the major initiatives was the implementation of the Goods and Services Tax (GST), a unified tax system that has streamlined India's complex tax structure, making it easier to do business in the country. He has also pushed for initiatives like Make in India,

Digital India, and Startup India, aimed at boosting manufacturing, digital infrastructure, and entrepreneurship, respectively.

PM Modi has placed a strong emphasis on infrastructure development, with a focus on improving connectivity, especially in rural areas. The government understands that it is not the nation that builds the roads, but it is the roads that build the nation. The road network has increased by 60 per cent in the last decade and has become the second largest in the world after the US, surpassing China's position. Projects like the Bharatmala Paryojana project for road development have improved connectivity to rural areas and boosted economic growth by generating employment opportunities and reducing travel time and transportation costs.

Over the last few years, the government has also taken some steady steps in the field of scientific achievements and cultural narratives. The success of the Chandrayan 3 launch on the moon's away end shows our growing potential in space technology and scientific exploration. The government's initiatives to revise history textbooks will produce a more culturally rooted generation with national pride and a sense of identity amongst them. During the COVID-19 pandemic, PM Modi faced several challenges which had a devastating impact on India's economy and healthcare system. However, under his leadership, Bharat could administer 2.2 billion doses of vaccine and supply it to the people along with 101 countries of the world. In 2014, India was the 10th largest economy, but by 2023, it became the 5th largest economy and soon will be the 3rd largest economy.

In his third term, PM Modi is expected to focus on the economy, creating jobs, and improving healthcare and education infrastructure. His government's budget for 2024 reflects these priorities, with increased allocations for healthcare, education, and infrastructure development. Overall, his third term is likely to be defined by continuity and change. The road ahead may be challenging, but with a strong mandate and a clear vision, P Modi is well-positioned to lead India towards a brighter future.

Beyond Borders: World Awaits the Historic Mandate

Anhad Jakhmola
Political consultant
and PhD scholar

The slogan 'Ab ki baar 400 paar' seems to be the new buzzword for the BJP as it aims to come back with a stronger sense of duty and loyalty to the citizens of India. The historic target of 400 seats set by Prime Minister Shri Narendra Modi has enthused the cadre and supporters alike. The slogan has made a desired impact with the push made by both print, social media, and TV channels.



Not only the people of India but even those outside, heads of state and tabloids in whatever creative manner of approach, feel the same. Even papers The Guardian has admitted to its popularity, albeit with an editorial grudge that PM Modi will come for the third term in power. One can always choose to read and understand whether those writing these articles are writing with some good intentions or not. Nevertheless, the realization has dawned upon them that opinionated pieces cannot undermine the ground reality.

Perhaps one of the best examples of a foreign leader who has not only accepted the eventual win but also made his wish to plan a trip to India is Russian President Shri Vladimir Putin. In his meeting with the foreign minister, Shri S. Jaishankar, in Moscow, he expressed his wish to travel to India later this year. He even invited PM Modi to Moscow. Another example is when PM Modi wished for the victory of the Russian President, wishing him to look forward to building a stronger relationship between both nations. This vote of confidence by Russia and directly by the Russian President is a welcome sign.

The next example is the assertion made by the Prime Minister at the Quad summit held in Japan in May 2023. He stated that India will be happy to host the Quad summit in 2024. The Prime Minister said this in the presence of the President of the US, Joe Biden, the Australian Prime Minister, Anthony Albanese and the Prime Minister of Japan, Fumio Kishida. Making a bold statement like this almost a year back is a sign of confidence backed by his governance record in the last ten years. So, making this kind of statement is in tandem with the strategy of boldness, and that goes well when the BJP stands by its expectations that are brought forward by the slogan "Abh ki baar 400 paar".

The PM has been repeatedly winning surveys that equate him to global leaders alike and has stamped his popularity over these years. Despite the type of press that likes to cover things partially, there is no stopping his electoral strategy. Add to that, various other surveys around eliminating extreme poverty and other areas of concern catered by the number

of schemes run by the government will propel the BJP to a historic victory. The active and robust diplomacy of PM Modi has countered all propaganda by the foreign press and motivated think tanks. It was actively seen in the way India hosted the G20 as well as the SCO in the same year. It is essentially due to PM Modi's leadership that the G20 resolution, termed the "New Delhi Resolution", was achieved. To get a consensus made during times of war and instability around the world is another aspect that nations wish to see more in numbers in 2024.

At the same time, while India maintains itself well with most actors across the board, it also highlights the issues in the United Nations. The example of the CAA being finally implemented is an important promise that the BJP, under the leadership of Prime Minister Modi, made and corrected a historical wrong done during partition. When some nations showed an uncanny form of interest in this, unlike in the past, India firmly and logically countered any interference.

As India awaits the next innings of Prime Minister Modi and his charismatic personality that shall lead the nation in its Amritkaal, the world has prepared itself to welcome him for a third historic term. The Global South views him as their leader in the international forum, the Russian Federation considers him a valuable friend, and the United States has increased its cooperation, viewing the enormous strides India has made under Prime Minister Modi. Even China, which, as said by the External affairs minister, shares a delicate situation at the LAC, has shown indications of dealing with India under his leadership.

The global arena awaits Prime Minister Modi's third term with the same excitement as the Indian voter does. "Abhi ki Baar, 400 paar" is a slogan that will resonate with those inside and outside the boundaries of Bharat.

Diaspora & Diplomacy: Uniting Global Indians for a Resurgent Bharat

Alok Virendra Tiwari

Chanakya Fellowship in Social Sciences at Chanakya University, Bengaluru.

Dr Parthiv N Mehta

MBBS, MD and advisor to multiple AI/ML-focused start-ups

Indian values of fraternity and integrity have been instrumental in shaping the country's journey to global eminence. It's crucial to reflect on the remarkable transformation India has experienced under Prime Minister Shri Narendra Modi's leadership as the nation approaches a new phase. Each term of the Modi government has not only steered the country toward progress but also enhanced India's standing on the global platform.

The government's strategic ventures have not just displayed India's potential but also established the groundwork for unparalleled growth and influence. As we consider the possibility of a third term for the Modi government, it becomes evident why this continuity is vital for India's ongoing emergence as a global leader.

India's rise on the global stage is rooted in its deep commitment to leverage the potential of its



diaspora. Prime Minister Modi's vision, reflected in initiatives like the Pravasi Bharatiya Divas (PBD) and PBD Convention, has built a strong bond between India and its spread. Platforms like the PBD Convention bring together thousands of delegates worldwide to facilitate idea exchange and collaborative projects, cultivating a sense of unity in diversity and resonating with global audiences.

Initiatives such as the Know India Programme (KIP) and Pravasi Teerth Darshan Yojana have successfully reconnected the younger generation of the Indian diaspora with their cultural roots. By immersing them in India's rich cultural heritage and facilitating visits to sacred sites, these initiatives have nurtured a sense of pride and connection among diaspora youth, strengthening cultural ties and showcasing India's inclusive approach to its spread.

The government's emphasis on education and skill development, illustrated through initiatives like the Scholarship Programme for Diaspora Children and the Global Initiative for Academic Network (GIAN), has positioned India as a hub for academic excellence and innovation. By attracting distinguished international faculty and offering scholarships to diaspora children, India is harbouring global collaboration in education and research, enhancing its soft power and diplomatic ties.

In addition to fortifying ties with the diaspora, the Modi government has demonstrated exceptional leadership in ensuring the welfare and protection of Indian citizens abroad. Initiatives such as the Pravasi Bharatiya Bima Yojana and the Vande Bharat Mission have provided financial security and timely assistance to Indian workers and citizens in distress, earning praise from the international community.

The government's pro-active approach to migration, exemplified through the India Centre for Migration and the Pre-Departure Orientation Training (PDOT), has facilitated safe and orderly migration and empowered migrants for successful integration abroad. The India Centre for Migration conducts

research to facilitate the migration process and address the challenges faced by migrants, promoting safe and orderly migration while protecting the rights of Indian workers abroad.

The Pravasi Bharatiya Bima Yojana insurance scheme offers financial security to Indian workers migrating abroad, providing coverage for various contingencies and instilling confidence among migrant workers. Additionally, the Pre-Departure Orientation Training (PDOT), under the Pravasi Kaushal Vikas Yojana, equips prospective migrants with essential skills and knowledge for successful integration abroad, contributing to the economic empowerment and social inclusion of Indian migrants in destination countries.

During the COVID-19 pandemic, the Vande Bharat Mission facilitated the repatriation of distressed Indian nationals stranded abroad, showcasing India's capacity for swift and effective crisis response. The mission's efforts earned accolades from the international community and fostered goodwill.

The prestigious Pravasi Bharatiya Samman Award recognizes the outstanding contributions of overseas Indians to India's development and global reputation. By honouring exemplary individuals, the award enhances India's soft power and influence and fosters partnerships with countries worldwide. India's remarkable progress over the past decade across economic, educational, financial, industrial, and technological domains has positioned it as a beacon of progress on the global stage. Through strategic initiatives and sustained efforts, India continues to lead the world through its success, resilience, and leadership.

As India moves forward under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, it is clear that a third term for the Modi government is vital for the country's continued progress and global leadership. As we look ahead to "Tisri Baar Modi Sarkar," let us renew our commitment to a resurgent India, poised to lead the world through its success, resilience, and unwavering leadership under Prime Minister Shri Narendra Modi.

Vision 2024: Forging Ahead with Tisri Baar Modi Sarkar

Rajarshi Roychowdhury

Study Circle In-Charge

BJYM West Bengal

"A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance..." These iconic words were recorded for posterity when Independent India's first Prime minister, Pandit Nehru, uttered them at the stroke of midnight on 15 August 1947.



History has been an impassioned judge, and these words somehow gained new resonance and meaning when they actually came alive on 26 May 2014 when the first prime minister to have been born in independent Bharat took oath as the 15th Prime minister of India. Before it, 25 years of policy paralysis, coalition compulsions and crippling corruption barring a five-year hiatus during the Vajpayee years, got India into the fragile five group of nations which were on the cusp of financial failure.

It was 30 years since the people of Bharat gave India a decisive government with a close to 2/3rd majority in the Lok Sabha. The nation had spoken, the mandate was decisive, the challenges were immense, the roadblocks were myriad, the brickbats were many, the bouquets were few, but the will to act was infinite & the Yugpurush at the centre of it all was undeterred as he always had been. PM Modi had the mandate to act, and act he did.

It is no secret that India is a young nation, yet it is an ancient civilisation. The youth is yearning for change & the change in Amrit Kaal must be decisive yet grounded on a firm foundation to give Bharat the energy to run a marathon towards a Viksit Bharat in 2047. A few path-breaking reforms during PM Modi's third term would firmly put India at a pole position.

While we are justifiably looking forward to reaping our demographic dividend, there is also a limit to the population that our land and its resources can sustain. A population control bill is needed for a sustainable future. A population growth rate of over 2.1 children per family is simply unacceptable to the vast majority of Indians in 2024. There should also be an Assam-like NRC for the rest of India, with foreign aliens who stay illegally whilst drawing government benefits should be detected, have their names deleted from the electoral rolls, and finally be deported to their country of origin.

The Prime minister has rightly urged parliament to strike down and repeal old and archaic laws that have no relevance today. Parliament has gone a long way and has recently replaced the colonial-era IPC, CRPC & the Indian Evidence Act with the BNS, BNSS & the Bharatiya Sakshya Act. The need of the

hour now is to amend the Income Tax Act, which is a paradise for lawyers and tribunals, with a simple and effective direct tax code that empowers the ordinary taxpayer and restrains the excesses of the taxman. It would also reduce the burden of regulatory compliances on business houses, which in turn would increase their productivity.

Devbhoomi Uttarakhand has recently enacted a pragmatic and progressive Uniform Civil Code, and Assam has recently banned the medieval practice of child marriage. The states blessed by Maa Ganga and the Brahmaputra have taken a vow to cleanse their states of social evils. Indian states must come forward to have parliament enact a single overarching uniform civil code to fulfil the dreams of the majority of the members of our constituent assembly and also realise the lofty principles enshrined within the directive principles of our constitution.

The framers of our constitution had envisioned a system of checks and balances for all three organs of the state. Unfortunately, the judiciary has become an opaque institution, with judges appointing judges, a huge pendency of cases and a 19th-century judicial apparatus clearly unequipped to face cases in the 21st century. In no other nation in the free world do judges appoint judges. The higher judiciary today is an ivory tower bereft of reservations and equal representation from weaker sections of society, including women. The striking down of the farsighted National Judicial Appointments Committee has seriously compromised the effectiveness and efficiency of the higher judiciary. A new set of judicial reforms is a pressing need of the hour.

Change is often a stubborn process till it achieves critical mass to break all the hastily erected barriers to stop an idea whose time has come. 2014 would perhaps go down as the year in which the green offshoots of change were visible on the Indian horizon, and today, it is looming large on the Indian sky, which no force on earth can hope to undo. What that decisive moment meant was summed up by the Guardian newspaper's editorial on 18 May 2014, which said that 18 May 2014 may well go down in history to the day when Britain finally left India.

From Vision to Victory: Modi's Third Mandate for a Resilient India

Akanksha Singh

The author is a Healthcare Policy Research Professional,
and has done her MA & LLB from Pune University

The slogan "Tisri Baar Modi Sarkar" (Modi government for the third term) has emerged as a dominant narrative in India's political discourse. Since assuming office in 2014, Prime Minister Shri Narendra Modi has steered India towards a path of transformation, guided by the principles of good governance and technological innovation. His leadership has been marked by a steadfast commitment to upholding the principles of Raj Dharma and laying the foundations of a modern-day Ram Rajya.

Firstly, it is important to acknowledge the significant achievements of the Modi government during its tenure. The government's focus on financial inclusion, which is a critical aspect of inclusive growth, has been a core agenda and a notable achievement. Through various initiatives like the Jan Dhan Yojana, the government has ensured that over 400 million Indians have access to banking services. It has not only improved the financial situation of millions of households but also increased their participation in the formal economy.

Moreover, the Modi government's commitment to infrastructure development has been instrumental in boosting economic growth. With projects like the Bharatmala Pariyojana, Sagarmala, and the Smart Cities Mission, the government has invested

significantly in the country's infrastructure, creating jobs and stimulating economic activity. Another area where the Modi government has shown progress is in the ease of doing business. The government's initiatives like Make in India, Startup India, and the Insolvency and Bankruptcy Code have made India a more attractive destination for businesses, both domestic and foreign.

Furthermore, the Modi government's focus on self-reliance and Atmanirbhar Bharat has gained momentum in the wake of the COVID-19 pandemic. The government's efforts to promote local industries and reduce dependence on imports have received widespread support. It not only creates jobs but also strengthens India's economic resilience. One of the hallmark achievements of the Modi government has been the successful implementation of Aadhaar. While India was not the pioneer in adopting such a system, the scale and efficiency with which Aadhaar was executed set a global benchmark.

The Aadhaar has revolutionized India's economic landscape by providing its citizens with a secure and universally accepted form of identification. It has facilitated faster access to essential services, including financial inclusion for millions previously excluded from the formal banking sector. Through Aadhaar-enabled initiatives, the government has



been able to streamline welfare delivery mechanisms, eliminate leakages, and ensure that benefits reach the intended beneficiaries directly.

The Digital India program, launched in 2015, seeks to bridge the digital divide by providing access to digital infrastructure, services, and literacy to all citizens, even in the remotest corners of the country. Under this initiative, significant strides have been made in areas such as e-governance, digital payments, and broadband connectivity, laying the groundwork for a knowledge-based economy.

Furthermore, the government's focus on infrastructure development, particularly in the realm of transportation and energy, has spurred economic growth and enhanced India's competitiveness on the global stage. Initiatives like the Bharatmala project for road connectivity and the Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) for power sector reforms have addressed longstanding bottlenecks and paved the way for sustainable development.

In the realm of foreign policy, Prime Minister Modi has been proactive in fostering closer ties with both traditional allies and emerging global powers. His diplomatic outreach has revitalized India's role as a key player in regional and international affairs, enhancing trade relations, promoting cultural exchanges, and strengthening strategic partnerships.

Investments in infrastructure development play a pivotal role in strengthening the backbone of the economy and enhancing productivity across sectors. The Atmanirbhar Bharat Abhiyaan prioritizes the creation of robust physical and digital infrastructure, including roads, railways, ports, and broadband connectivity, to facilitate seamless movement of goods and services and enable efficient functioning of businesses.

Equally crucial is the reform of systems and processes to foster a conducive environment for innovation, investment, and growth. The government's efforts to streamline regulatory frameworks, ease of doing business, and promote

transparency and accountability are geared towards enhancing the ease of conducting business and attracting both domestic and foreign investments.

A vibrant demography characterized by a young and skilled workforce presents a significant opportunity for driving economic growth and innovation. The Atmanirbhar Bharat Abhiyaan seeks to harness the demographic dividend by investing in education, skill development, and entrepreneurship, thereby unlocking the full potential of India's human capital.

Furthermore, stimulating demand through targeted interventions and promoting consumption-led growth is vital for sustaining economic momentum and generating employment opportunities. The government's initiatives to boost rural and urban consumption, enhance purchasing power, and revitalize key sectors such as agriculture, MSMEs, and healthcare are integral to creating a demand-driven economy.

The conceptualization of Amrit Kaal, the 25 years from 2022 to 2047, symbolizes India's journey towards becoming a developed and independent nation. Atmanirbhar Bharat serves as the blueprint for realizing this vision, laying the foundations for a resilient, prosperous, and self-reliant India by 2047.

As India strides confidently towards the future, the Atmanirbhar Bharat Abhiyaan serves as a beacon of hope and inspiration, rallying the nation towards a common goal of self-reliance and prosperity. With Prime Minister Shri Narendra Modi's visionary leadership and unwavering commitment, India is poised to emerge stronger and more resilient, reaffirming its rightful place on the global stage. His unwavering commitment to national development, coupled with a forward-looking vision for a digital and inclusive India, sets the stage for a transformative decade ahead. As the nation looks towards the future, it is imperative to build upon the successes of the past and address the challenges with renewed vigour and innovation. With Prime Minister Modi at the helm, India is poised to realize its full potential and emerge as a global powerhouse in the 21st century.

Forging Ahead with Modi: A Third Term for India's Golden Era

Bharat Sharma

Advocate, High Court of Delhi

In an era defined by transformation and tenacity, India, under the prime ministership of Shri Narendra Modi, has embarked on a journey of unprecedented reform and rejuvenation. As we stand on the precipice of a historic election, the call for a third term for the Modi government is not merely a political campaign but a clarion call for the continuation of a vision that has redefined the essence of governance, development, and national pride. This narrative seeks to unfold the myriad dimensions of Modi's governance that beckon a third term as a conduit to India's golden age.

Prime Minister Shri Narendra Modi's blueprint for India, "Viksit Bharat", sets the nation on an ambitious path of transformation, striving for a perfect balance between rapid economic growth, social equity, and environmental stewardship. This

forward-thinking vision proposes a unique melding of cutting-edge technology with India's rich cultural traditions, emphasizing the upliftment of marginalized communities and the democratization of opportunities across the societal spectrum. Central to this vision are major strides in infrastructure enhancement, digital advancements, and industrial revitalization, aiming to elevate India's stature on the global stage. Equally critical is the preservation of India's cultural legacy and the promotion of national unity, fostering a society that is deeply rooted in its historical values while simultaneously steering towards a progressive horizon. In essence, PM Modi's envisioned "Viksit Bharat" transcends mere economic achievements, focusing instead on cultivating a vibrant, well-educated, and empowered populace poised to propel India into a future filled with prosperity and promise.

A Stronghold of Sovereignty and Security

The Modi administration has been emblematic of assertive and robust leadership, particularly in matters of national security. The decisive abrogation of Article 370, rendering Jammu and Kashmir an integral part of India without the shadows of temporary provisions, stands as a testament to Modi's commitment to national integration and sovereignty. Furthermore, the unwavering stance against terrorism and extremism, underscored by surgical strikes and diplomatic pressures, has fortified India's security apparatus, instilling a newfound sense of safety and pride among its citizens.

The Economic Resurgence

Navigating through the choppy waters of global economic downturns, the Modi government's economic policies have been a beacon of resilience and strategic foresight. Initiatives such as the Goods and Services Tax (GST) and the Insolvency and Bankruptcy Code have streamlined business operations and fortified the banking sector,



respectively. The 'Make in India' campaign, dovetailed with policies favouring startup ecosystems and digital economy, has positioned India as a global manufacturing and fintech powerhouse, propelling it towards becoming the world's third-largest economy.

Social Inclusion and Empowerment

The narrative of development under Modi's tenure is replete with stories of social inclusion and empowerment. From the Jan Dhan Yojana, which brought banking to the doorsteps of millions, to the Ujjwala Yojana, liberating numerous women from the clutches of unhealthy cooking practices, the government's schemes have been instrumental in elevating the quality of life for the marginalized. The Ayushman Bharat scheme stands as the world's largest healthcare initiative, offering a new lease of life to the underprivileged.

Infrastructure and Technological Leap

The Modi government's ambitious infrastructure projects, including the Bharatmala and Sagarmala projects, aim to revolutionize India's roadways, waterways, and overall logistics, promising a future of seamless connectivity and economic efficiency. The push towards digital India has democratized information access, making government services more transparent and accessible, thereby fostering a digitally empowered society.

The Cultural Renaissance

To reclaim India's rich cultural legacy and historical narratives, the Modi government has undertaken numerous initiatives that celebrate the nation's heritage. The international recognition of Yoga, the revival of traditional arts and crafts, and the restoration of historical sites have not only boosted cultural tourism but have also reinstated a sense of national pride and identity among Indians.

The construction of the Ram Mandir in Ayodhya marks a historic chapter in India's modern history, significantly influenced by the policies and environment fostered by Prime Minister Narendra Modi's government. Under Modi's leadership, the long-standing dispute, which had been a source of religious and political contention for decades,

found a new direction towards resolution. The government's role in facilitating the process, including the formation of a trust to oversee the temple's construction and the allocation of land, underscores PM Modi's role in actualizing a project deeply ingrained in the cultural and spiritual ethos of India. This move is seen by many as a fulfilment of a key cultural aspiration of the people of India.

Governance and International Stature

The hallmark of the Modi government has been its transparent, accountable, and citizen-centric governance model. The government's relentless crusade against corruption, coupled with reforms in governance practices, has restored faith in the administrative machinery. On the international front, Modi's diplomatic acumen has elevated India's global stature, fostering strategic alliances and positioning India as a pivotal player in shaping the new world order.

Education and Health: The Pillars of a New India

Recognizing the critical role of education and health in nation-building, the government has introduced the National Education Policy (NEP) 2020, aiming to overhaul the educational landscape to meet the demands of the 21st century. In health, the expansion of healthcare infrastructure and services, especially in the wake of the COVID-19 pandemic, has showcased the government's ability to manage unprecedented crises effectively.

As India stands at the crossroads of history, the choice is not merely between different political entities but between divergent visions for the future. The Modi government's tenure has been a testament to transformative leadership underpinned by a vision of inclusivity, development, and global prominence. Electing Modi for a third term would not only be an endorsement of this vision but also a step towards realizing the dream of a resurgent India, poised to reclaim its status as a global leader and a beacon of democracy, development, and peace. The journey thus far has been momentous, but the path ahead, under the continued leadership of Modi, promises to usher in an era of unparalleled prosperity and global accolades for India.

Judicial and Legal Reforms: The Case for a Decisive Third Term

Krithika Chandrashekara

The author is a practising lawyer from Karnataka



India's judicial system has been greatly bolstered, attributable in large part to the government led by Prime Minister Shri Narendra Modi. The administration run by PM Modi has gone to great lengths in stringing aspirations and achievements together to build up a line of conduct that will help determine areas in which Indian laws were lacklustre. All three branches of government - the legislature, executive, and judiciary comprise the trinity; each of their responsibilities must be coherent in order to maintain the virtue of sovereignty.

The practice of courts today is a derivative of the catastrophic embrace of imperialistic abstractions, which has indeed flawed the legal regime in our country. There have been parallels drawn between the emergence of the Indian common law system and the introduction, application, and subsequent mutation in the English language. However, the Anglo-Saxon concepts in various enactments are now value-wise arcane. In addition to this, a sense of accountability on the part of the judiciary is showing signs of life vis-à-vis the unfolding of indigenous administration of justice.

Law and justice are usually regarded as mutually exclusive, and our courts often get referred to as "Courts of Justice." Nevertheless, the goals of justice and the law aren't always mutually exclusive. The Apastambiya Dharma Sutra observes that a court of justice is a forum where contrasts between truth and falsity are determined in accordance with the rules of law. Justice is the foundation of each state, and there are multifarious dimensions to permeate this to ensure fair and equitable implementation. Hence, the logical corollary is to achieve integral development of juridical order where the idea of justice and the public trust in the judiciary are harmonized.

The ultimate need of the hour is to particularize and correct the challenges stacked before the judges and evolve an apparatus to eliminate the inefficacy that plagues legal proceedings. In view of undertaking the function of formulating laws that push for novel strides in the legal field, the BJP has shown positive dedication. It can be conceded that a considerable amount of laws have been put into practice to address the miseries of the masses. Our judiciary, which at one time was seen as the weakest wing of the state, is now being restructured as the agency for better enforcement of legislation.

By utilizing the judiciary as the tactful beacon, an equal set of remedies can be crafted with the help of technologically advanced methodology along with appropriate legal innovation. To buttress this point, the PM has, from time to time, pitched the idea of making Alternative Dispute Resolution Systems a top priority. There is a core of truth in the statements made by the PM, and he has averred that his government is striving to create new legal norms and models to invigorate easy access to justice.

Socially relevant and purposive enactments have been devised, namely, the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016; the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017; the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019; and so forth. In the same fashion, the future will be a testament to a series of experiments in an effort to familiarize, culminate, collaborate, and help lessen the gap between the corridors of power and the commoners.

A cursory glance at Arun Jaitley's blunt comments regarding the collegium system reveals that the process of selecting judges was devoid of transparency. The task at hand in the establishment of the National Judicial Appointments Commission (NJAC) has been one of the pivotal moments in India's judicial history. The commission is an inclusive body comprising the CJI, two senior-most judges from the Supreme Court, two distinguished individuals from the social sphere, and the Minister of Law and Justice. By cutting off what was the sole

authority the judges had to select other judges, the commission inscribed to protect the judiciary against the allegations of crony favouritism. The tragic fact is that a five-judge bench wrote off this hard effort.

The success registered in criminalizing the practice of Triple Talaq is yet another significant leap piloted by the Narendra Modi government; an enactment was passed in this regard, which gave it a solid foundation. The vice of a Muslim man's unilateral right to give an instantaneous divorce to his wife was tossed out by a constitutional bench of the Hon'ble Supreme Court. Emphasis was added as to how the fundamental rights of women were being strengthened, and thus, the objective of removing an indelible stain of female subjugation was secured.

On the ouster of three timeworn criminal laws, PM Modi proclaimed, "Earlier, the focus was on punishment and penal aspects. Now, the focus is on ensuring justice. Therefore, citizens have a sense of assurance rather than fear." The theme that persists throughout this is to reshape the current legal framework. This overhaul pinpoints rendering the system a breeze, the most benign thing being its victim-friendly approach. Much evidently, this is a symbolic move away from the remnants of the colonial era.

Suppose we are to deduce from the analogy of these instances. In that case, the judicial set-up in the country has begun to replenish itself with an abundantly clear objective to cast off crusty layers in the adjudication process. Ahead of the 2024 polls, it is in our best interests to ensure that PM Modi will be entrusted power with a two-thirds majority in order to prevent protracted complexities by allowing trials to proceed quickly, to let the legislature and the executive have a say on the appointment of judges, to defeat anything that would jeopardize women's welfare, and, finally, because a powerful head of the government envisions a systemic salvation of the Republic.

Modi's Global Parivar Says 'Tisri baar Modi Sarkar'

Deepakshi Bhardwaj

Geopolitical Researcher, Bachelor of
International Relations & Economics,
Beloit College, USA

In the anxious backdrop of mounting geopolitical uncertainties and the high-stakes super-election year of 2024, the world is anchored in India's stability, in other words, anchored in 'Modi ki Guarantee.' PM Modi is India's embodiment of 'Vishwa Mitra' – the world needs him just as much as Bharat.

International Relations was always considered an esoteric subject, far, far away from the common man of Bharat – until the Modi magic happened. In a relieving shift away from the practices of Nehruvian foreign policy, PM Modi brought the principles of 'Antodaya' and Integral Humanism to India's foreign policy forefront. For the first time, India's foreign policy fully embraced realism, pragmatism, and nationalism.

As PM Modi pushed for 'Local to Global' while encouraging small and big businesses in every part of India to aim to export to the world, another phenomenon took shape where foreign affairs went from 'global' to 'local,' as they started capturing

young India's attention in even the most remote parts of Bharat.

Antodaya and a voice for the global south

PM Modi exemplified Antodaya during the COVID-19 pandemic when the countries of the global south found a reliable friend in India. India took a massive humanitarian initiative to deliver vaccines to countries in need which were left in the cold by the so-called developed world. India has been a proactive participant in leading humanitarian efforts across the globe when it comes to war situations or disaster relief.

PM Modi harnessed the innate diversity of India and extrapolated it to the rest of the world when 'sabka sath, sabka vikas' went global. Under his leadership, India has pressed for re-inventing multilateral institutions that work for everyone. India has assertively expressed its dissatisfaction with global financial institutions as well. India has become a voice of the global south with forwarding agendas that exhibit equity, mutual benefit, and peaceful coexistence. With its strong support for the G4 model for reforms in the United Nations Security Council, India is paving the way for many countries to be confident in their place in the world as it challenges the archaic power structures that no longer reflect the reality of the world today.

Modi's Civilizational Bharat – a gift that keeps on giving

PM Modi's leadership breathed new life into Bharat's ancient identity. Not only did Indians become more confident in their abilities, but the world also recognized what Bharat has to offer. From Yoga and Ayurveda to innovation in space tech and solar power, PM Modi brought India to the centre stage.

The Indian diaspora is increasingly confident under PM Modi. There is a sense of collective



consciousness when it comes to the sentiment of 'India-first' that now extends beyond the physical contours of our country. Indians are venturing out into the world with a renewed sense of self-belief and a strong faith in their government back home. As India's External Affairs Minister, Dr S Jaishankar, puts it – "Every Indian out in the world has the confidence that we have his or her back." It is a prime example of a civilizational connection that his government has achieved by increasing Bharat's cultural footprint – expanding the global understanding of Bharat beyond economics and politics.

Economic 'bright spot' and a 'reliable' partner

The geoeconomics landscape looks grim in the wake of slowing economies, supply chain disruptions, economic weaponization, subpar growth rates, and geopolitical tensions. Against this backdrop, India's economic gait is agile and steady. The world is calling India the "global bright spot, a powerhouse of growth and innovation." PM Modi's policies not only kept the Indian economy afloat; they also allowed the world to shift to a more reliable supply chain and a promising investment destination – Bharat.

PM Modi's emphasis on 'para-diplomacy' has also allowed the world to engage with India on a much more meaningful level. Since the success of his Gujarat model decades ago, many Indian states have directly engaged in the international sphere, attracting significant investments and introducing state-specific expertise to the world. This phenomenon lets Bharat show its full self to the globe without the homogenization of Indian culture while still forwarding the interests of the Indian state. It exemplifies PM Modi's commitment to cherishing and fostering diversity with full respect for regional uniqueness in India.

India has signed several MoUs with countries aiming to partner with India in its growth story, showcasing the immense momentum that India's jump is creating in the world. Indonesia and UAE have agreed to de-dollarize bilateral trade with India, rooted in the 'Modi ki Guarantee.' Several free trade agreements have been signed or are underway, including those of the EU, EFTA bloc, the

UK, and Australia. It demonstrates how the world is looking to India to spur global growth.

Making India a voice of reason

PM Modi made India's global voice undiluted and rooted in Indian principles. Whether it was the Russia-Ukraine crisis, where he became the only leader to say, "This is not an era of war," or it is India's nuanced stance on the Israel-Hamas conflict where India stands against both terrorism and collective punishment, PM Modi has expressed India's voice with compassion and integrity.

PM Modi's unequivocal stance on terrorism has brought the principle of 'Integral Humanism' into policy. When it comes to protecting India's territorial integrity against cross-border terrorism, PM Modi has walked the talk on bolstering resilience against terrorism, leaving no space for romanticism. His position is clear – a feat against terrorism in any country is a global win.

PM Modi's focus on strengthening defence extends beyond the national domain. The new India has become the primary security provider in the Indian Ocean Region, providing secure sea lines of communication and safeguarding transnational trade, stability, and peace. The world needs India to ensure security in the hotbed of the new age, 'Great Power Competition.'

A guiding light for the world

Ten years in power, PM Modi has become the most loved global leader with solid approval ratings and a voice that carries immense weight. Today, the world sees PM Modi as a leader capable of guiding global consensus, which is inclusive and democratic. The G20 summit was a testament to PM Modi's ability to forge consensus where severe friction exists. When the world is watching doom unfold, whether it is climate crisis, cybersecurity, or territorial expansionism, Modi's India is strongly poised to be at the forefront of guiding global cooperation, dispute resolution, and maintaining peace and stability in the world.

As more than half the globe goes to the polls this year, the world's eyes are set on India, awaiting the dynamic leader's power-packed third term.

Heritage Reborn: A Call for Continuity into the Third Term

Sanjana Sinha

Sociology Graduate,
University of Delhi
Currently working with Dalit
Indian Chambers of Commerce
& Industry (DICCI)

The cultural heritage of a society is the culmination of its values, traditions, and shared experiences, fostering a sense of unity and purpose. India's culture, which has flourished for more than 5000 years and acts as a uniting force beyond political and physical borders, is fundamental to the country's unity. Hinduism is an integral part of Indian culture, including not just religion but also an entire value system, which is the foundation of the Indian civilisation. The values of Hinduism, including its central doctrine of coexistence and Vasudhaiva Kutumbakam, are embedded in Indian society. The rich fabric of Indian cultural legacy is enriched by the subcultures that have arisen and developed over time, all of which have their roots in Hinduism.

The Bharatiya Janata Party has taken responsibility for bringing about remarkable transformations in Indian politics and society, all the while expressing their opinions and stances in accordance with the views of the times. The rejuvenation, repair, and



renovation of sacred temples as a means of revitalising Indian culture is crucial to defining the character and strength of a country. Prime Minister Shri Narendra Modi's cultural awakening has spurred a current concentrated effort to revitalise and renovate ancient temples. The actions taken by PM Modi demonstrate a strong dedication to reviving India's cultural legacy. These efforts are shown by the building of the Ram Mandir in Ayodhya, the Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal in Ujjain, the embellishment of Kedarnath, and several other projects. These projects go beyond religious significance; they signify the resurgence of cultural nationalism and pride.

These noteworthy accomplishments have led to a rise in visitors to the historic temples, which are now providing more amenities and a more contemporary appearance for their followers. Several initiatives, including the Pilgrimage Rejuvenation, Spirituality Augmentation Drive (PRASAD), and Augmentation Yojana (HRIDAY), have been introduced by the Modi administration. The renovation of the temples reflects the timeless Sanatan Dharm and spiritual energy. The magnificence of Varanasi and the Kashi Vishwanath are remarkable. The Modi government also took the initiative to link all four pilgrimage sites; Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath through Char Dham Pariyojana. The grand statue of Adi Shankaracharya is a symbol of India's unity. Today, the cave where the prime minister meditated has become a pious site. Similarly, the Mahakal Lok in Ujjain has demolished all previous records of visiting devotees with its magnificence.

The magnificent Abu Dhabi temple is more than just a place of worship; it is a representation of the common history of all people. It represents the spiritual aspect of ties between the United Arab Emirates and India and depicts the affection shared by the people of Arabia and India. The unexpected development of land being provided for the temple in the United Arab Emirates, an Islamic nation, highlights the significance of diplomatic efforts and collaboration in promoting cultural and religious peace on a worldwide scale. The BAPS saints' unwavering devotion and the Modi government's

collaborative efforts are responsible for this mission's successful completion.

Nevertheless, PM Modi's projects go beyond building and restoring temples. They provide a comprehensive strategy for a cultural rebirth, encompassing the return of stolen artefacts to their rightful owners, the development of religious tourism, and the preservation of historical landmarks. Under his guidance, there has been a resurgence of interest that appeals to a wider range of Hindus than just religion. Just 13 stolen artefacts in total were recovered between 1976 and 2013, while 235 cultural and historical artefacts were brought back from overseas after 2014. An age-old custom has been brought back to life with the Sengol's installation in the new Parliament building. Notable efforts have also been made to restore India's lost cultural heritage and emblems of national dignity.

The fact that the United Nations (UN) has recognised June 21 as Yoga Day and accepted yoga as India's gift to the world is evidence that Prime Minister Modi is using global platforms to promote Indian culture and its core values. It is also remarkable that he is working to restore yoga and Ayurveda to their former position as civilisations. These days, yoga is the foundation of a disciplined and healthy lifestyle, attracting the attention of people worldwide. Some estimates place the number of yoga practitioners worldwide at over 300 million. Yoga is also connected to the recent surge in the health and fitness industries.

PM Modi's leadership has been crucial in this cultural revival, helping people rediscover their heritage and paving the way for a new period of cultural rebirth. The government's nine-year accomplishments are unparalleled. Every ministry has set goals, ranging from international security, economic advancement, and global respect for India to world-class infrastructure development and programs for the care of the impoverished. PM Modi must return to power a third time to ensure that the arduous task he has undertaken reaches fruition.



Consolidating Progress: Why Modi's Vision Warrants a Third Term

M Priyananda Sharma

MPhil in Security Studies from Central University of Gujarat & Columnist

In May 2014, Narendra Modi led the BJP to secure a historic victory in the Indian general elections, marking the beginning of what came to be known as the Modi era in Indian politics. With the successful completion of two terms, the prospect of a third term for the Modi government raises numerous questions and considerations.

Before delving into the prospects and challenges of a third term for the Modi government, it is essential to reflect on the achievements of the previous two terms. During his tenure, Modi implemented several ambitious initiatives such as Make in India, Swachh Bharat Abhiyan, and the Goods and Services Tax (GST). Additionally, the government focused on infrastructure development, digitalization, and

foreign policy initiatives, including the Act East Policy and strengthening ties with major powers like the United States.

A third term under Modi's leadership could prioritize economic rejuvenation post-pandemic, focusing on infrastructure development, investment promotion, and job creation. Continuation and expansion of social welfare schemes such as Ayushman Bharat, PM-Kisan, and Ujjwala Yojana to uplift the marginalized sections of society. Further integration of technology in governance through initiatives like Digital India, fostering innovation and digitization across sectors. Continuation of a proactive foreign policy aimed at enhancing India's global stature and strengthening strategic

partnerships. Emphasis on sustainable development and environmental conservation through initiatives like the International Solar Alliance and Swachh Bharat Mission.

The government faces the daunting task of reviving the economy amidst global uncertainties, addressing issues like inflation, fiscal deficit, and unemployment, and managing diverse socio-cultural dynamics to foster inclusive growth and social harmony. It also has to implement administrative reforms to improve governance efficiency, transparency, and accountability. Tackling environmental challenges such as air pollution, water scarcity, and climate change through effective policy measures and public participation are other challenges. Navigating complex geopolitical realities and managing relations with neighbouring countries amidst regional security challenges will test the Modi government in its third term.

We have also witnessed the Modi government taking initiatives and efforts to transform the education sector by implementing a new education policy that holds immense potential to transform education and foster inclusive development. The establishment of new IIMS and IITs represents a significant step towards democratizing access to quality higher education and promoting regional development in India.

Keeping in mind the peaceful and diplomatic resolution of the Ram Mandir issue by the Modi government reflects India's commitment to upholding the principles of justice, plurality, and democratic governance. By respecting the rule of law, engaging in dialogue, and promoting communal harmony, the government has set a precedent for resolving contentious issues through peaceful means, fostering unity and progress in the nation. Such sustained efforts are needed to ensure that the spirit of inclusivity, tolerance, and mutual respect prevails, laying the foundation for a harmonious and prosperous society.

Also, the announcement of the revocation of Article 370 by the Modi government was a watershed moment in Indian history, with far-reaching

implications for the region of Jammu and Kashmir, India's federal structure, and the broader geopolitical landscape.

The growth rate of vote share for the BJP and its allies in the previous Lok Sabha elections indeed highlights the public's support of the Modi government. The BJP's vote share increased from 31% in 2014 to 37.36% in 2019, showcasing a significant rise in public support over the five years. Similarly, the National Democratic Alliance (NDA), led by the BJP, saw an increase in vote share from 38.5% in 2014 to 45% in 2019. These statistics indicate solid proof of public endorsement for the policies, leadership, and governance of the Modi government during its first term and subsequent re-election. The rise in vote share suggests that the electorate perceived the government's performance positively and expressed their support through their votes in successive elections.

The increased vote share for the BJP and NDA reflects confidence in the government's initiatives, including economic reforms, infrastructure development, social welfare schemes, and national security measures. It also signifies approval of Prime Minister Shri Narendra Modi's leadership and vision for the country. Overall, the growth in vote share for the BJP and its allies in the 2019 Lok Sabha elections underscores the public's welcoming response to the Modi government's agenda and actions, reinforcing its mandate to govern and implement policies for the benefit of the nation.

The prospect of a third term for the Modi government presents both opportunities and challenges. While the government has demonstrated its commitment to transformative governance and development agenda, it also faces formidable tasks in addressing economic, social, and environmental concerns. The success of a potential third term would depend on the government's ability to build on past achievements, address existing challenges, and adapt to evolving socio-political dynamics, ultimately contributing to India's progress and prosperity.

सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं

आशीष रावत
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)



किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए कुछ ऐसी नीतियों को धरातल पर लाना अति-आवश्यक है जो पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद आपको बेहतर परिणाम दे सके। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने देश को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सेवा करने का किसी को भी अवसर मिलता है, तो सभी के मन में यही रहता है की कैसे यहां की बुनियादी व्यवस्थाओं को सुधारें मगर हर कोई ये कर नहीं पाता है, जो नरेन्द्र मोदी ने गत दस वर्षों में करके दिखाया है। मोदी सरकार के प्रभावी प्रयासों से लगभग पच्चीस करोड़ लोगों गरीबी रेखा से बाहर आये हैं, जो गत 75 वर्षों में मुमकिन नहीं हो पाया। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक के सफर को देखा जाए, तो सरकार ने सबसे अधिक फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर किया है। मोदी सरकार ने पिछले बजट में ही कैपेक्स के लिए दस लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। अगर सरकार के आंकड़ों को देखें तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने 11.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। कैपेक्स का फायदा इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट जोड़ता है। इससे रोजगार पैदा होता है, साथ ही इकोनॉमी की ग्रोथ तेज होती है। पहले की सरकार ने अपने दस वर्ष में जितनी सरकारी नौकरियां दी थीं, उससे लगभग डेढ़ गुना अधिक सरकारी नौकरियां मोदी सरकार ने अपने दस वर्षों में दी हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अब तक के कार्यकाल के दौरान लिए गए नोटबंदी, जीएसटी, तीन तलाक कानून, सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना, नागरिकता संशोधन कानून, रेल बजट का आम बजट में विलय, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम महिला किसान ड्रोन केन्द्र, पीएम कौशल विकास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे निर्णयों ने देश की स्थिति को सुधारने का काम किया। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने जनधन योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की भी सौगात देशवासियों को दी। मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने का काम किया। उन्होंने गरीबों को मुफ्त राशन देने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा, वन्दे भारत ट्रेन और नए संसद भवन की सौगात भी देशवासियों को दी। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के सबसे बड़े संकट में थी तब दुनिया के सामने मोदी ने एक मिसाल पेश की। मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क टीके लगवाए। ऐसे गम्भीर समय में भारत ने कई देशों को निःशुल्क टीके भी दिए। कोरोना महामारी के उपचार के लिए अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सुधार किया गया।

देश के कई प्राचीन मंदिरों के कायाकल्प के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्प शक्ति रही है। दस वर्षों में अयोध्या से उज्जैन तक, काशी से केदारनाथ तक प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अवधनगरी में सिर्फ राम मंदिर नहीं बना है बल्कि पूरे

इलाके का कायाकल्प भी हुआ है। मोदी ने आध्यात्म के साथ विकास को भी जोड़ा। इसका असर ये है कि आज अयोध्या से लेकर आबू धाबी तक भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है। डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5जी सेवाओं की शुरुआत की। हर क्षेत्र में गत दस वर्षों में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो गई, एम्स की संख्या 6 से बढ़कर 24 हो गई, 723 से बढ़कर 1472 विश्वविद्यालय हो गये, 16 आईआईटी संस्थान की संख्या अब 23 हो गई और 13 से बढ़कर 20 आईआईएम हो गये, ये सब सम्भव मोदी की दूरदृष्टि के कारण ही हो पाया है। लगभग दस वर्ष पूर्व तक कुछ सौ ही स्टार्टअप्स होते थे और आज करीब सवा लाख पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं जो देश के 600 से अधिक जिलों में फैले हैं और टीयर-2, टीयर-3 शहरों के नौजवान स्टार्टअप क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं जोकि प्रधानमंत्री की विजन का ही परिणाम है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक आयोजन के दौरान आगामी पांच वर्ष का रोडमैप देशवासियों के सामने रखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगामी पांच वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे, अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे, भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे, बुलेट ट्रेन से लेकर वन्दे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे, वॉटर-वे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। इसके अतिरिक्त भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते हुए देखेंगे, भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान और गगनयान की सफलता देखेंगे, देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर के उदय देखेंगे, भारत की सोलर पावर को घर-घर में पहुंचता हुआ देखेंगे, भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैनुफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे, सेमीकंडक्टर मिशन, हार्डड्रोजन मिशन का जमीन पर प्रभाव देखेंगे और निर्णायक नीतियां बनते व निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक भारत पूरी तरह से विकसित, आत्मनिर्भर और दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। इसके साथ ही 2025 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी और 2040 तक एक व्यक्ति को चन्द्रमा पर भेजने का संकल्प भी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एक नारा दिया है, 'सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं'। ये अभियान बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को हकीकत में बदला है। राजनीतिक विश्लेषक भी स्वीकार करते हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, मोदी की गारंटी से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आये हैं, यही वजह है कि भाजपा को चुनाव दर चुनाव भव्य विजय प्राप्त कर रही है। आज देश के माहौल और तमाम सर्वेक्षण स्पष्ट बता रहे हैं कि नरेन्द्र मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने जा रही है।



**BHARATIYA JANATA
YUVA MORCHA**